



पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

दिसंबर 2022



आज़ादी का
अमृत महोत्सव



भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्



एक पृथ्वी
एक परिवार
एक भविष्य



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(Punjab & Sind Bank / A Govt. of India Undertaking)

राजभाषा विभाग

प्रधान कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022



बैंक के प्रधान कार्यालय में 31 अक्टूबर, 2022 से 06 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस दौरान बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, रोहिणी, नई दिल्ली में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें श्री सुरेश एन पटेल (केंद्रीय सतर्कता आयुक्त), श्री अरविंद कुमार (सतर्कता आयुक्त), श्री पी डैनियल (सचिव-केंद्रीय सतर्कता आयोग) को आमंत्रित किया गया था।

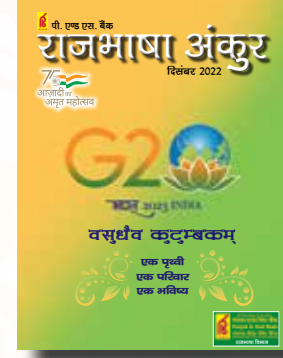
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008



दिसंबर 2022

मुख्य संरक्षक

श्री स्वरूप कुमार साहा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक

श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र

कार्यकारी निदेशक

डॉ. रामजस यादव

कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री कामेश्वर सेठी

महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक एवं प्रकाशक

श्री निखिल शर्मा

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री देवेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

श्रीमती मोनिका गुप्ता, प्रबंधक (राजभाषा)

श्री मोहन लाल, राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : ho.rajbhasha@psb.co.in

पंजीकरण सं.: एफ.2(25) प्रैस. 91

(पत्रिका प्रकाशन तिथि : 15/01/2023)

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटरर्स

ए 33/2, साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया,

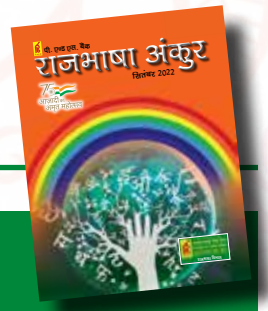
गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश

फोन नं. : 98112 69844

ई-मेल: jainaooffsetprinters@gmail.com

विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल/विषय-सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 तथा विश्व हिंदी दिवस	4-6
5.	प्रधान कार्यालय स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	7
6.	भारत में प्रथम जी-20 सम्मेलन	8-10
7.	रूस और यूक्रेन युद्ध के बढ़ते प्रभाव	11-13
8.	कार्टून-कोना	13
9.	बैंकिंग क्षेत्र में साइबर अपराध के बढ़ते जोखिम एवं रोकथाम के उपाय	14-17
10.	ग्राहक के मुख से	18
11.	सेवानिवृत्ति	19
12.	उप निदेशक (राजभाषा) का पत्र	20
13.	दिल्ली बैंक नराकास में बैंक	21
14.	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति का भावनगर दौरा	22-23
15.	चैला-चिमटा और सवाल - व्यंग्य	24-25
16.	काव्य-मंजूषा	26-27
17.	बैंक में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन	28-29
18.	प्रधानमंत्री आवास योजना	30-33
19.	अंचल कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022	34-35
20.	मेरी खजुराहो यात्रा	36-39
21.	भारत में ग्रीन फाइनेंस	40-42
22.	नराकास उपलब्धियां/गतिविधियां	43
23.	नई शाखाएं	44



आपकी कलम से

हमें आपके बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" की प्रति प्राप्त हुई— धन्यवाद! इस पत्रिका में प्रकाशित आलेख 'डिजिटल भुगतान और यूपीआई', 'सोशल मीडिया – एक नए युग का आरंभ', 'हरित वित्त (ग्रीन फाइनेंस)' एवं अन्य रचनाएं पठनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं। इसमें बैंक की गतिविधियों एवं अन्य खबरों का व्यवस्थित रूप से समावेश किया गया है। इसके प्रकाशन से जुड़ी टीम का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

आशा है भविष्य में भी आप अपने स्तर पर हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन व तत्संबंधी गतिविधियों से हमें अवगत कराएंगे।

—उमानाथ मिश्र

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), बैंक ऑफ बड़ौदा

मुझे बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" का सितंबर-2022 अंक प्राप्त हुआ, जिसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद! पत्रिका में प्रकाशित सामग्री हमेशा की तरह बहुत ही आकर्षक एवं प्रेरणादायक लगी। पत्रिका में प्रकाशित विषयों जैसे राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका, डिजिटल भुगतान और यूपीआई, सोशल मीडिया एक नए युग का आरंभ आदि रचनाओं ने हृदय में विशेष स्थान बनाया। इसके अतिरिक्त "काव्य-मंजूषा" के अंतर्गत प्रकाशित कविताएं बहुत ही सुंदर लगीं।

इस पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्रों के माध्यम से बैंक के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न अंचल कार्यालयों में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन एवं इस पत्रिका के माध्यम से बैंक को प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों हेतु पत्रिका के संपादक मंडल/प्रकाशक/विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।

— रशपाल सिंह

आंचलिक प्रबंधक गुरदासपुर

आपके बैंक की हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का सितंबर 2022 का अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद! पत्रिका का कलेवर, साज-सज्जा और प्रस्तुति अत्यंत ही आकर्षक, रमणीय तथा उच्च कोटि की है।

पत्रिका में शामिल समस्त लेख, कविताएँ अत्यंत ही रोचक और पठनीय हैं। इस पत्रिका की विषय-वस्तु का निर्माण बहुत ही शिद्दत और मंथन करके किया गया है। पत्रिका में सम्मिलित 'अब और देर नहीं', 'राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका' जैसे लेख राजभाषा हिंदी के महत्त्व पर प्रकाश डालने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने और उसके कार्यान्वयन पर बल देते हैं।

डॉ. चरनजीत सिंह जी ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बिलकुल सही ही कहा है— "यदि हम वास्तव में भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार के इच्छुक हैं तो हमें अपनी समस्त क्षेत्रीय भाषाओं को संग लेकर चलना होगा।"

इसके अतिरिक्त 'हरित वित्त', 'डिजिटल भुगतान और यूपीआई', 'सोशल मीडिया-एक नए युग का आरंभ' जैसे बैंकिंग, सोशल मीडिया आदि की जानकारी प्रदान करने वाले ज्ञानवर्धक लेखों ने भी ध्यान आकृष्ट किया है। सुश्री गगनदीप कौर जी ने अपने लेख 'भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष' में आजादी के 75 वर्ष में भारत में हुए मूलभूत सकारात्मक-नकारात्मक परिवर्तनों, प्रगति आदि की चर्चा करते हुए निष्कर्ष के रूप में बिलकुल सटीक लिखा है कि — "बेहतर समाज एवं राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। तभी जाकर एक बेहतर भारत और 'न्यू इंडिया' के सपने को साकार किया जा सकेगा।" लेखों के अलावा अंक में शामिल कविताएँ भी काफी बोधगम्य, रोचक और आकर्षक हैं।

'राजभाषा अंकुर' के इस संग्रहणीय अंक के लिए पूरी संपादकीय टीम बधाई की पात्र है। आशा है कि आगे भी हमें ऐसे ही उत्कृष्ट और पठनीय अंकों का रसास्वादन करने का अवसर मिलता रहेगा। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

डॉ. गुलाबचंद यादव
महाप्रबंधक — राजभाषा
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
प्रधान कार्यालय, मुंबई

संपादकीय



प्रिय साथियो,

नवीन साज-सज्जा में पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का दिसंबर-2022 अंक आपके सक्षम प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मन के भावों, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ-साथ विभिन्न व्यावसायिक, साहित्यिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार का यह सशक्त मंच है। पत्रिका, हमें कार्मिकों की सृजनात्मक क्षमता से भी परिचित कराती है और आपस में जोड़ने का काम भी बड़े सजगता के साथ करती है।

पत्रिका के संपादन का दायित्व मुझे जून, 2021 में मिला लेकिन पत्रिका से मेरा जुड़ाव काफी पहले से रहा है। मुख्य राजभाषा अधिकारी बनने के बाद भी मेरा प्रयास रहा कि संपादन कार्य के अतिरिक्त मैं किसी न किसी रूप में पत्रिका के लिए लेखन कार्य से जुड़ा रहूँ। पत्रिका के जितने भी अंकों के संपादन का अवसर मुझे मिला, उनमें मेरा यह प्रयास रहा कि पत्रिका में गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों का समावेश हो। मुख्य राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए मुझे संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के निरीक्षण कार्यक्रमों से भी रू-ब-रू होने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय का विशेष सानिध्य व सहयोग मिला। पत्रिका के माध्यम से आप सभी से संवाद करने का आनंद अप्रतिम होता है और संभवतः मुझे यह अनुभूति शायद ही कभी हो। संपादक के रूप में अपनी बात रखने का यह मेरा अंतिम अवसर है क्योंकि मैं बैंकिंग सेवा से 31 दिसंबर, 2022 को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं एक पाठक व लेखक के तौर पर इस पत्रिका के माध्यम से आप सभी से जुड़ा रहूँगा।

पत्रिका के इस अंक में समसामयिक लेखों को विशेष रूप से स्थान प्रदान किया गया है। 'कार्टून-कोना' एक विशेष संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। 'काव्य-मंजूषा' के अंतर्गत विविध कविताओं को शामिल किया गया है। पत्रिका के 'सितंबर-2022' अंक के लिए हमें ढेर सारी प्रतिक्रियाएं मिली जिनके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ।

पत्रिका जब तक आपको प्राप्त होगी तब तक नव वर्ष 2023 का आगमन हो चुका होगा। मैं कामना करता हूँ कि नववर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और प्रगति लेकर आए। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव, पत्रिका के उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए हमें निरंतर प्रोत्साहित करती है। कृपया पत्रिका पर अपना स्नेह बनाएं रखें।

पुनः शुभकामनाओं सहित!

कामेश सेठी
(कामेश सेठी)

महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी



वीरेन्द्र कुमार यादव

विश्व हिंदी सम्मेलन तथा विश्व हिंदी दिवस

दीर्घकालीन प्रवासी भारतीय गाँधी जी 9 जनवरी 1915 में 21 वर्ष के प्रवास के बाद भारत आते ही भाषा के काम में लग गए। वे भली प्रकार समझ गये थे कि भारतीयों की सार्वभौमिक अखंडता – एकता एवं पहचान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की एक भाषा होना जरूरी है। इस कार्य की पहल उन्होंने 1918 में दक्षिण भारत से शुरू की, जहाँ उन्होंने 1928 में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। राष्ट्र में हिंदी को जन-जन तक पहुँचाने एवं भारतीयों को जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया था।

विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की कल्पना का मूल आधार उन भावनाओं से अनुप्राणित होता है जिनके अंतर्गत महात्मा गाँधी ने वर्ष 1936 में भारत के हिंदीतर राज्यों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से अपनी कर्मस्थली वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। इसी वर्ष नागपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे, हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई थी। इस अधिवेशन में राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गाँधी, पं. जवाहर लाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ जमनलाल बजाज, काका साहेब कालेलकर, माखनलाल चतुर्वेदी तथा कई अन्य सुविख्यात विद्वानजन शामिल थे।

विश्व हिंदी सम्मेलनों की वर्तमान श्रृंखला की वैचारिक शुरुआत सितंबर, 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नायक अनंत गोयल शेवडे की प्रेरणा एवं मधुकर राव चौधरी के प्रयास से हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गाँधी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और भारत सरकार ने मई 1974 में पूर्ण सहयोग एवं समर्थन



का आश्वासन दिया। इस प्रकार भारत की सार्वभौमिक अखंडता एकता के लिए तथा हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से 10 जनवरी, 1975 में नागपुर से विश्व हिंदी सम्मेलन की जो शोभा यात्रा प्रारंभ हुई उसने सितम्बर, 2012 में जोहान्सबर्ग में अपना नौवाँ पड़ाव पूरा कर लिया। 10 जनवरी को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के शुरुआत होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा मेरे प्रस्ताव पर विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति की बैठक में दिनांक 8 जून, 2005 को प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए स्वीकृत हुआ। एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हुई। दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ परंतु देश स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में अभी तक सामूहिक रूप से उसे मनाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। कुछ कार्यालयों में अवश्य शुरुआत हुई है।

दूसरा तथा तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन क्रमशः 1976 मॉरीशस तथा



विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरीशस
WORLD HINDI SECRETARIAT, MAURITIUS





1983 नई दिल्ली में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रधान मंत्रित्वकाल में और उन्हीं की प्रेरणा व प्रोत्साहन में आयोजित हुआ। फिर चौथे 1993 में मॉरीशस, पांचवें 1996 में त्रिनिडाड, छठे 1999 में लंदन, सातवें जून 2003 में सूरीनाम, आठवें 13-15 जुलाई 2007 को न्यूयार्क में तथा 22-24 सितम्बर, 2012 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन, 10 वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन 10-12 सितम्बर 2015 भोपाल, 11वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त 2018 मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुईस में आयोजित हुआ, अगला 12वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन 16-17 फरवरी 2023 में फिजी में होने जा रहा है।

विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के प्रचार-प्रसार, हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा दिलाने तथा विश्वमंच पर उसे मान्यता दिलाने आदि के सपने देखे गए और उन्हें पूरा करने के संकल्प लिए गए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के 37 वर्षों के बाद क्या हुआ उन सपनों और संकल्पों का जबकि विश्व का हर छठा व्यक्ति हिंदी बोलता है?



**बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी।
सिंहासन पर अंग्रेजी है, देखकर दुनिया हॉंसी,
देख कर दुनिया हॉंसी, हिन्दीदा बनते चपरासी,
अफसर सारे अंग्रेजीमय, अवधो या मदरासी,
कह कैदी कविराय, विश्व की चिंता छोड़ो,
पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो।**

यह कसक है उस कवि की जो देश की राजनीति के शिखर पुरुष रहे हैं भारत के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। यह कसक उस दौर की है जब वे आपातकाल के दौरान कारागार में थे और मॉरीशस में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन (1976) संपन्न हो रहा था। इतिहास ने अंगड़ाई ली और फिर एक ठसक सामने आई—

**गूँजी हिन्दी विश्व में स्वप्न हुआ साकार,
राष्ट्र संघ के मंच से हिन्दी की जयकार,
हिन्दी की जयकार, हिन्द हिन्दी में बोला,
देख स्वभाषा-प्रेम, विश्व अचरज से डोला,
कह कैदी कविराय, मेम की माया टूटी,
भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी।**

आपातकाल के कैदी कविराय आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी 4 अक्टूबर, 1977 को भारत के विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में हिंदी में भाषण देकर दुनिया के सामने अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना के सूत्रधार बने। फिर 26 वर्षों के बाद 2003 में उसी विश्व पंचायत राष्ट्र संघ के मंच से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हिंदी में भाषण देकर मान्यवर वाजपेयी जी ने अपनी मनसा और नीति को स्पष्ट कर दिया। फिर भी कसक और उसके बीच कहीं कोई छोर अनछुआ सा लगता है, जो विवेचन-विश्लेषण और विचार मंथन की अपेक्षा रखता है।



अब तक इन सम्मेलनों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त की है। जैसे महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। प्रारंभ से सरकारी अफसरों के घेराव में आता रहा है जिससे कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। इसके बाद हैदराबाद में स्थापित अंतरराष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय नित्य नये प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरीशस में की गयी है। इसे भी सुचारू रूप में व्यवस्थित कर गतिशीलता प्रदान करने की आवश्यकता है।

हमें एक समुचित एवं सुनियोजित योजना बनानी है जिससे भारतवर्ष सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आगे आ सके। योजना को मूर्तरूप देने के लिए भाषायी समन्वय के साथ हमारी शिक्षा को, भारतीय भाषाओं के माध्यम से होना पड़ेगा और यह तब तक संभव नहीं हो पायेगा, जब तक हम संपूर्ण भारत के लिए संपर्क भाषा का चयन, प्यार स्नेह एवं समरसता के सिद्धान्तों पर नहीं कर लेते हैं।

मेरे विचार से यह एक चिंता का विषय है कि भारत जैसा राष्ट्र, जो मनीषियों एवं संतुलित विचारकों से भरा हुआ है। पिछले कई दशकों में कोई नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में नहीं अर्जित कर पाया है जबकि इजरायल जैसे छोटे से राष्ट्र ने 1948 से अब तक 12 ऐसे पुरस्कार अपनी झोली में डाल लिये हैं। यह राष्ट्र बड़े ही

गर्व के साथ अपना सारा काम-काज अपनी राष्ट्रभाषा हिब्रू में करता है। अगर भारत की अनेक भाषाओं को सही बढ़ावा दिया जाता है तो कोई कारण नहीं है कि हम कई अन्य गुरुवर टैगोर जैसे साहित्यकारों को खोज न निकाले। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की आर्य एवं द्रविड़ भाषाओं में ऐसे अनेक साहित्यकार अब भी हैं जो सही वातावरण एवं प्रोत्साहन के मिलते ही नोबेल पुरस्कार भारत को दिला सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा के बढ़ते हुए वर्चस्व ने भारत की समस्त भाषाओं को कमजोर बनाया है जिसके कारण राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई है। हिंदी हमारे मन में है लेकिन वह अब हमारे व्यवहार में होगी तथा आने वाली पीढ़ियों में भी हिंदी के प्रति प्रेम बना रहे। विश्व हिंदी सम्मेलन के समय हमें पूर्व स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा तथा एक क्रियान्वयन समिति के गठन के साथ कार्यक्रमों को समयबद्ध बनाना होगा। वास्तव में तभी विश्व हिंदी सम्मेलनों के उद्देश्यों को पूर्ण करने में गति आयेगी। हम वे ही प्रस्ताव स्वीकार करें जिन्हें हम क्रियान्वित कर सकें, अन्यथा प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

सदस्य – हिन्दी सलाहकार समिति, भारत सरकार
सह अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय हिन्दी परिषद, भारत

रचनाकारों से निवेदन

रचनाकारों से निवेदन है कि बैंक के प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही तिमाही हिंदी गृह-पत्रिका "राजभाषा अंकुर" में प्रकाशन हेतु लेख भेजते समय लेख के अंत में अपना नाम, शाखा/कार्यालय का नाम व पता, मोबाइल नंबर तथा अपना बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अवश्य लिखें। इसके साथ ही लेख के संबंध में मौलिकता प्रमाण-पत्र और अपना फोटो भी उपलब्ध कराएं। सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य उपरोक्त के अतिरिक्त अपने घर का पता तथा स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) का भी उल्लेख करें।

—मुख्य संपादक

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (अक्टूबर-दिसंबर 2022)



प्रधान कार्यालय स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 07 दिसंबर, 2022 को माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रधान कार्यालय के समस्त विभागों के महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक तथा अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बैंक में हिंदी कार्यान्वयन, गतिविधियों तथा उपलब्धियों पर सदस्यों ने विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर माननीय कार्यकारी निदेशक महोदय ने अपने कर कमलों से बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" के सितंबर 2022 अंक का विमोचन किया।



डॉ. कौशलेन्द्र

भारत में प्रथम जी-20 सम्मेलन



मानव सभ्यता के विकास क्रम को देखे तो यह सहज ही ज्ञात होता है कि कभी पत्थरों से आग जलाने वाले मानवों ने कितनी प्रगति कर ली है। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव ने दुनिया के देशों की आपसी दूरियां मिटा कर सभी को एक कुटुंब की तरह बांध दिया है। इतिहास में कभी साम्राज्यवाद ने तो कभी बाजारवाद ने दो भिन्न-भिन्न राष्ट्रों और संस्कृतियों के मिलने के मार्ग को प्रशस्त किया। पिछले 100 वर्षों के मानव के इतिहास को देखे तो साम्राज्यवाद की नीतियों ने मानव सभ्यता के विकास क्रम को दो बार गंभीर तरीके से झकझोरा है।

प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध की परिणीतियों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक देश, दूसरे देश के साथ सहयोगात्मक भाव के साथ नहीं रह सकता? जब यह वसुंधरा हम सबकी है और हम सबको इस पर रहना है तो क्या एक समान सोच और एक समान लक्ष्यों के साथ नहीं चल सकते? इसी सोच ने दुनिया के देशों में संगठन बनाने पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी राष्ट्र ढूँढने पर एक वैचारिक क्रांति ला दी। वैज्ञानिक आविष्कारों के अवांछनीय उपयोग और पूंजीवादी व्यवस्था की खामियों ने देशों के मध्य विषमता को पैदा किया। कुछ देश अमीर से अमीर होते चले

गए और कुछ देश गरीब से गरीब होते चले गए। आर्थिक दृष्टि से इस विषमता को दूर करने के लिए शीर्ष संपन्न देशों ने प्रयास किया और कई संगठन भी बनाए।

ऐसा ही एक संगठन वर्ष 1999 में जी-20 के नाम से बनाया गया। इसमें सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के प्रमुख भाग लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में की गई थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण शुरु किया गया था। इस संगठन को बनाए जाने का एक प्रमुख उद्देश्य विश्व के विकासशील देशों और विकसित देशों के मध्य संवाद स्थापित कर वैश्विक, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को सरल बनाना है। आज इस संगठन के पास दुनिया के पेटेंट का 95%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी के 65% का प्रतिनिधित्व है। इस संगठन के देशों के नाम हैं— अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की,

ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन। अभी देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जी-20 की चर्चा प्रमुखता से की जा रही है। इसका कारण 15-16 जुलाई 2022 को बाली (इंडोनेशिया) में हुए जी-20 बैठक की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई और इस प्रकार 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जा रहा है। बाली में सम्पन्न 17वीं जी-20 बैठक में रिकवर, टुगोदर, रिकवर स्ट्रॉगर विषय के तहत आयोजित किया गया। अभी जी-20 में प्रमुखतया 08 विषयों पर बल दिया जाता है। वो हैं- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनंस, ग्लोबल माइक्रोनोमी पालिसी, इंटरनेशनल फाइनंशियल आर्टिटेक्चर, वित्तीय समावेशन, सस्टनेबल फाइनंस, हेल्थ फाइनंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनंशियल सेक्टर रिफोरम्स।

बाली में सम्पन्न 17वीं जी-20 बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। ये सभी विषय ऐसे हैं जो भारत के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन विवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हमारे भारत के लिए भी प्रासंगिक हैं। जी-20 के गठन का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को संतुलित और स्थिर करना था। अभी विश्व में भारत की स्थिति मध्यम आय वाले देशों में बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी राष्ट्र या राष्ट्रों का संघ विश्व में किसी भी प्रकार के सुधारत्मक पहल को बिना भारत को शामिल किए नहीं कर सकता। जी-20 के सदस्य देशों ने भी विश्व में बढ़ती भारत की आर्थिक, सामरिक एवं डिजिटल शक्ति को समझा और जी-20 की अध्यक्षता सौंपी। निश्चित ही ये हम भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है।

ऐसा प्रथम बार ही हो रहा है जब किसी ऐसे वैश्विक अग्रणी संगठन की अध्यक्षता भारत को प्रदान की गई है और भारत में इसकी बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। जबकि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के किसी संगठन का सदस्य होना ही अपने आप में बड़ी बात मानी जाती रही है तब तो भारत को इसका नेतृत्व करने का मौका दिया जाना, भारत के लिए एक उपलब्धि है। भारत को इसकी अध्यक्षता दिया जाना भारत की विदेश नीति की सफलता को भी तस्दीक करता है। प्रमुख विदेशी मीडिया ने इसके पीछे जो वजह बताई वो हमें जानना जरूरी हैं। हाल के वैश्विक संकटों के मध्य भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा जो बेहद स्पष्ट और संतुलित रवैया रखता है। जिसकी मित्रता जितनी यूरोप-अमेरिका से है उतनी ही रूस से भी है। प्रमुख अमेरिका मीडिया सीएनएन ने भारत को एशिया में सबसे सशक्त और तेजी से उभरती शक्ति बताया है। इसने लिखा कि जी-20 की हालिया बैठक के साझा घोषणापत्र में इस बात को साफ-साफ कहा गया कि वर्तमान दौर युद्ध का नहीं है और यह वही बात थी जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने



रूसी राष्ट्रपति के समक्ष एक बैठक में बोला था। यह संकेत करता है कि विश्व अब भारत के हर बात को कितनी गंभीरता से लेता है। कोरोना महामारी में भी भारत ने जिस प्रकार सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की, वह विश्व में भारत के कद को बढ़ाता है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि "मुझे यकीन है कि बुद्ध और गाँधी की धरती पर जब जी-20 के नेता मिलेंगे तो हम दुनिया में शांति का एक मजबूत पैगाम देंगे।" भारत ने जिस तरह से विश्व के ज्यादातर मजबूत देशों के विपरीत शांति और युद्ध विराम की वकालत की है वो भारत को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। देश या तो यूक्रेन के साथ खड़े हैं या फिर रूस के साथ। भारत ने इस बैठक में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि यह मंच दुनिया के देशों का राजीतिक मंच न बन जाए जहां विश्व के गरीब देश, विकासशील देशों की समस्याएं सुनने समझने के बजाए आपस में ही उलझ पड़े। भारत ने अन्य सभी विकासशील देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि रूस-यूक्रेन विवाद के अलावा भी अन्य मुद्दों पर आम सहमति बन सके। बैठक में अन्य देश भारत से यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत भी इस विवाद में अब किसी न किसी देश के पक्ष में निर्णय लेगा, लेकिन भारत ने युद्ध की विभिषिका को मुद्दा बनाया तथा एक शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। इन्ही सब कारणों से भारत को जी-20 बैठक का नेतृत्वकर्ता बनाया गया।

भारत 1 दिसंबर, 2022 से लेकर 30 नवंबर, 2023 तक जी-20 का मेजबान होगा। भारत के विभिन्न राज्यों में इस संगठन की 200 बैठकें होंगी। भारत में पहली बार ऐसा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है। भारत सरकार के लिए यह चुनौती भी है और अवसर भी। जहां एक तरफ इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन का कुछ खास अनुभव नहीं होने की चुनौती है वहीं दूसरी तरफ भारत इस मंच का उपयोग अपनी क्षमता और प्रबंधन शक्ति के प्रदर्शन के रूप में करेगा। भारत को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बैठक के एजेंडा पर विचार करने का अवसर मिला है और भारत इसका भरपूर लाभ भी उठाएगा। यह सच है कि भारत की उपलब्धियों पर पश्चिमी देशों का ध्यान जरा देर से ही जाता है। बड़े पैमाने पर भारत में एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना, सभी गरीब नागरिकों को राशन मुहैया कराना, स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना, कोरोना

टीकाकरण आदि ऐसी ही उपलब्धियां है जिन्हें वैश्विक मंचों पर चर्चाओं में शामिल किया गया परंतु अधिकांश पश्चिमी देश भारत के प्रति अपनी पूर्वाग्रही दृष्टि के कारण इन उपलब्धियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। भारत के पास यह एक सुनहरा मौका है कि वो अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करेगा।

भारत ने अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिश्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियाई विकास बैंक आमंत्रित संगठन है। जरा सोचिए कि इतने वृहत पैमाने पर भारत का आतिथ्य जब स्वीकार किया जाएगा, भारत की उपलब्धियों को जांचा-परखा और समझा जाएगा तब भारत को लेकर जो पिछली अवधारणाएं हैं वो तो निश्चित ही समाप्त हो जाएंगी। भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा जहां भारत का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और ठोस होगा। भारत जहां एक तरफ अपनी घरेलू उपलब्धियों को, अपनी चुनौतियों को और अपने लक्ष्यों को प्रकट कर सकेगा वहीं दूसरी तरफ विश्व के प्रति जो वसुधैव कुटुंबकम और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का चिंतन है उसे भलि भांति विश्व के समक्ष रख सकेगा। जी-20 के अध्यक्ष को नीतिगत तौर पर कोई औपचारिक शक्ति नहीं मिलती, परंतु मेजबान होने के कारण अध्यक्ष देश का प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है। कूटनीति के कई अहम पहलू में एक मेजबानी का पहलू भी आता है। भारत की मेजबानी अगर आकर्षक, संतोषप्रद और प्रभावी रहती है तो इससे भारत की स्थिति और मजबूत होगी। विदित है कि जी-20 की अपना कोई स्थाई सचिवालय नहीं है, इसका प्रबंधन ट्रोइका के द्वारा किया जाता है। ट्रोइका में पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष शामिल होते हैं। भारत में होने वाले बैठक के इस ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। भारत ने इस बैठक में **“एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य”** के थीम पर विमर्श को सकेन्द्रित किया है। पूर्व विदेश सचिव हर्ष ऋंगला को भारत का मुख्य जी-20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। जी-20 की एक विशेष बात है कि इसमें विशेष राष्ट्रों को विशेष विटो शक्ति के उपयोग का प्रावधान नहीं है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में है इसलिए इस समूह में फैसले आम सहमति और नियत अवधि में ले लिए जाते हैं।

भारत सरकार, राज्यों की सरकारें और आम नागरिक भी इस बैठक को लेकर उत्साहित हैं। पूरे देश में जन-जागृति के लिए कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। शहरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कई स्तरों पर बैठकों का दौर जारी है। पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, सुविधा एवं अन्य प्रकार की जरूरी सेवाओं को लेकर मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार किया जा रहा है। जैसे हम अपने घरों में किसी



अतिथि के आने से पूर्व साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण करते हैं वैसे ही जी-20 के बैठक के शुरू होने से पूर्व पूरे भारत को सजाना है, तैयार करना है। एक नियोजित तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। इसमें हम नागरिकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिक ही देश की पहचान होते हैं, वो ही देश का निर्माण करते हैं। हमें भी यह प्रण लेकर चलना है कि इस बैठक की अभूतपूर्व सफलता में हम सभी से जो कुछ भी अपेक्षित सहयोग होगा, वो हम निश्चित ही करेंगे क्योंकि हम भारत के लोग, भारत के गौरव और यश के लिए सदैव से ही समर्पित हैं और रहेंगे।

— प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय दिल्ली—

प्रतिक्रिया

बैंक पत्रिका राजभाषा अंकुर का सितंबर 2022 अंक मिला। पत्रिका के रंग, रूप और कलेवर देखकर मन प्रसन्नित हो उठा। कभी मैं भी इस पत्रिका के संपादक मंडल में था परंतु तब न तो इतनी तकनीकी सुविधाएं थी और न ही उच्चाधिकारियों का स्नेह था जो अब मिलता हुआ दिख रहा है। चित्रों और कैप्शन का संयोजन बहुत आकर्षक है। काव्य-संध्या का आयोजन एक अभूतपूर्व आयोजन था। इसे हर साल कराएं और दिल्ली के अलावा भोपाल, लखनऊ में इस प्रकार के आयोजन हों। भोपाल के लिए मेरी निःशुल्क सेवाएं सदैव बैंक के साथ हैं।

संपादक और संपादन मंडल को साधुवाद। शुभकामनाएं!

—कुलवंत सिंह शेहरी
सेवानिवृत्त प्रबंधक (राजभाषा)



अवधेश नारायण सिंह

रूस -यूक्रेन युद्ध के बढ़ते प्रभाव

शांति बलपूर्वक नहीं रखी जा सकती, यह केवल समझदारी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

– अलबर्ट आइनस्टाइन

मानवीय सभ्यता के इतिहास में हिंसा व युद्ध लगभग अनिर्वार्य रूप से मौजूद रहे हैं। समय के साथ मनुष्य ने इसके दुष्प्रभावों को समझा परंतु अब तक छुटकारा नहीं पा सके हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध ने एक बार पुनः मानवीय सभ्यता को शर्मसार कर दिया है। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो परंतु एक बात तो पूर्णतः सिद्ध होती है कि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है। रूस व यूक्रेन के बीच संघर्ष ने भी बहुत नुकसान किया है और यह दिन व दिन विकसित होता जा रहा है। इस विवाद से अब महाशक्तियों के बीच भी जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। यह संघर्ष 2014 में शुरू हुआ जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस व रूस समर्थक सेनाएं शामिल थीं और दूसरी तरफ यूक्रेन। युद्ध, क्रीमिया की स्थिति व डोनबास के कुछ हिस्सों पर केंद्रित है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। वैश्विक महामारी कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई है। उसके द्वारा विश्व के अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा था और उसके पश्चात अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर आ रही थी परंतु उसके दौरान इस युद्ध और संघर्ष के कारण जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं, वो भी प्रभावित हुई है।

संघर्ष के कारण

रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध के कई कारण हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन, रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है।

➔ **अलगाववादी आंदोलन:** इन दो देशों के मध्य युद्ध का एक और कारण अलगाववादी आंदोलन भी है। पूर्वी यूक्रेन का डोनबास

क्षेत्र (डोनोत्स्क और लुहान्सक क्षेत्र) वर्ष 2014 से ही रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। यूक्रेन इसके लिए रूस को दोषी ठहराता है। इसके अतिरिक्त रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त कर लिया था जोकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्र पर कब्जा का दृष्टांत है।

➔ **यूक्रेन की नाटो सदस्यता :** यूक्रेन ने नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। रूस ने इस तरह के कदम को "रेड लाइन" घोषित किया है। इसके अतिरिक्त रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल न किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई भी ऐसा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसने देशों को गतिरोध में छोड़ दिया है जिससे दसियों हजार रूसी सैनिक, यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं।

➔ **यूरो-मैडल आंदोलन:** यूरो-मैडल (यूरोपीय स्कावायर) यूक्रेन में प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की लहर थी, जो 2013 में



शुरु हुई थी क्योंकि सरकार यूरोपीय संघ की तुलना में रूस के करीब थी।

➔ **शक्ति का संतुलन** : जब से सोवियत संघ का विभाजन हुआ है, रूस और पश्चिमी देशों में इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए देशों ने अधिक प्रभाव के लिए संघर्ष किया है।

वर्तमान परिदृश्य : रूस और यूक्रेन के खिलाफ शुरु की गई जंग को करीब नौ-दस महीने का वक्त पूरा हो गया है। इस जंग में



न केवल रूस और यूक्रेन ने अपना बहुत कुछ खोया है बल्कि पूरी दुनिया को भी अच्छा-खासा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन जैसा देश इस वक्त लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। रूसी सैनिकों को भी नुकसान हो रहा है और बाकी दुनिया खाने की कमी, बढ़ती महंगाई, परमाणु युद्ध की आशंका और इस युद्ध से उत्पन्न अन्य चुनौतियों से जूझ रही है। युद्ध के जल्दी खत्म होने के कोई आसार नहीं दिखाई देते। रेड क्रॉस ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि यूक्रेन संकट ने पूरी दुनिया के मानवीय व्यवस्था को झटका दिया है और दुनिया भर में आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के लिए संगठन की क्षमता पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के अध्यक्ष फ्रांसेस्को रोकका ने अगस्त -22 में कहा है कि "इसने लोगों को मुश्किल वक्त पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इस तरह से लड़ाई जारी रही तो भोजन और ईंधन की बढ़ती कीमत और गहराते खाद्य संकट का प्रभाव बढ़ जाएगा।"

इसके अतिरिक्त मौत का वास्तविक आंकड़ा काफी अधिक होने की संभावना है लेकिन जो आकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार 24 फरवरी, 2022 को जंग शुरु होने के बाद से 5587 आम नागरिकों एवं 7890 सैनिकों की मौत हुई है। ओएचसीएचआर के अनुसार अधिकतर नागरिकों की मौत रूस के हवाई तोप और मिसाइल हमलों से हुई है। 22 अगस्त को यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल वैलेरी

जालुज्मी ने बताया है कि यूक्रेन में लगभग 9000 यूक्रेन के सैनिक मारे गये हैं। अमेरिकी खूफिया जानकारी में बताया गया है कि यूक्रेन में रूस के लगभग 15000 सैनिकों की मौत हो गई है और तीन गुना ज्यादा घायल हो गये हैं। सन् 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान सोवियत संघ के जितने लोगों की मौत हुई, ये आंकड़ा उसी के बराबर है।

रूस- यूक्रेन संघर्ष का भारत पर असर

- ◆ तेल की कीमतों पर दबाव।
- ◆ केंद्र पेट्रोलियम पर ₹32.09/लीटर और डीजल पर ₹31.08/लीटर कर लगता है।
- ◆ भारत की तेल जरूरतों का 85% आयात।
- ◆ गैस, पेंट्स, रसायन, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, विमानन जैसे कई उद्योगों पर प्रभाव।
- ◆ सेमिकन्डक्टर चिप्स का अभाव।
- ◆ प्लास्टिक, रेफिन और एपाक्सी एडहेसिव, उर्वरक एवं अन्य पर मुद्रास्फीति का दबाव।
- ◆ वैश्विक कीमतों में वृद्धि से भारतीय के निर्यात पर प्रभाव।
- ◆ सरकारी खरीद में गिरावट और भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक में कमी।
- ◆ वनस्पति तेल, पाम तेल और कपास की कीमतों पर प्रभाव।
- ◆ निवेश पर प्रभाव।
- ◆ भारत में मुद्रास्फीति बढ़ी है जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है।
- ◆ इस संकट से स्वच्छ ऊर्जा बाजार को लाभ हो सकता है क्योंकि फॉसिल फ्यूल और आज की ऊर्जा गैर-नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित है परंतु अब सरकार का रुझान नवीकरणीय उर्जा को बढ़ाने की तरफ अग्रसर है। अतः हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ते देख सकते हैं।
- ◆ इसके अतिरिक्त भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बुलाने का संकट इसके लिए भारत सरकार ने मिशन गंगा चलाया है। अब तक लगभग 15000 से अधिक भारतीय छात्रों को निकाला जा चुका है।

विश्व पर असर

कई यूरोपीय देशों की गैस पाइपलाइनों के माध्यम से रूसी ऊर्जा पर निर्भरता।

- ◆ रूसी टैंकों पर प्रतिबंध के चलते आपूर्ति बाधित, तेल कीमतों पर वृद्धि।

- ◆ कूड तेल \$110-115/बैरल।
- ◆ परिवहन- समुद्री नौवहन और रेल यातायात पर प्रभाव।
- ◆ आपूर्ति श्रृंखला – कारखाने, बंदरगाह और फ्रेट यार्ड बाधित।
- ◆ खाने योग्य तेल, फूड सप्लाई, बढ़ती कीमतें, ऑटोसेक्टर भी इससे प्रभावित हुआ है।

भारत का रूख

08 अप्रैल 2022 को द हिंदू में प्रकाशित "Ukraine And The Anatomy Of India's Neutrality" लेख पर आधारित – भारत अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्ताव से भी दूर रहा जिसमें यूक्रेन के विरुद्ध रूस की आक्रमकता की कड़ी निंदा की गई थी। टी.एस.त्रिमूर्ति जी यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यू.एन.एस.सी में रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने 2020 के युद्ध विराम 2014 के मिन्स्क समझौते व नौरमेडी प्रक्रिया के लिए अपना समर्थन दोहराया है।

वैश्विक रूख

अमेरिका, यूरोपीय संघ, नाटो ने अब तक किसी के ऊपर पुख्ता कदम नहीं उठाया है केवल आर्थिक बहिष्कार किया है। यूरोपीय संघ और जी-7 विभिन्न प्रकार के समर्थक की पेशकश करते हुए हथियारों, खुफिया, नकदी और रसद की आपूर्ति और यूक्रेनी सैनिकों के प्रशिक्षण से लेकर रूसी अर्थव्यवस्था को अपंग करने के इरादे से गंभीर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन जिन्होंने यूक्रेन के साथ जब तक युद्ध चलेगा तब तक साथ खड़े होने की कसम खाई है। इसके अतिरिक्त रूस को कमजोर करना यूक्रेन युद्ध का छिपा हुआ एजेंडा है।

इस परिस्थिति का व्यावहारिक समाधान मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने में है। इस प्रकार अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश रूस व यूक्रेन के मध्य वार्ता को पुनः आरंभ करने एव सीमावार सापेक्ष शांति बहाली के लिए मिन्स्क समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

ऑचलिक प्रबंधक, भोपाल



प्रदीप राय
सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक

कार्टून कोना





स्नेहा जायसवाल

बैंकिंग क्षेत्र में साइबर अपराध के बढ़ते जोखिम एवं रोकथाम के उपाय

हमारा समाज, बैंक, अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे इत्यादि कंप्यूटर नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी समाधान पर काफी हद तक निर्भर हो गए हैं। यह कोई रहस्य नहीं रह गया है कि साइबर अपराध दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध संभावित रूप से अधिक विनाशकारी होते जा रहे हैं क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता बहुत बढ़ गई है। भारत 2020 में सबसे अधिक साइबर अपराध वाला देश था जिसकी राशि 4.5 मिलियन थी। आज साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि साइबर हमले शारीरिक हमलों की तुलना में सस्ते, सुविधाजनक और कम जोखिम वाले होते हैं। साइबर अपराधियों को केवल एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा बहुत कम खर्चों की आवश्यकता होती है। वे भूगोल और दूरी से अप्रतिबंधित हैं।

साइबर अपराध एक कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से किए गए आपराधिक आचरण को संदर्भित करता है। कम तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्तियों या लोगों के छोटे समूह और प्रतिभाशाली डेवलपर्स और विशेषज्ञों के साथ दुनिया भर में अत्यधिक संगठित आपराधिक समूह साइबर अपराध से जुड़े हो सकते हैं। क्रिमिनल या हैकर्स जो पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादातर साइबर क्राइम करते हैं। साइबर अपराध में व्यक्ति और संगठन दोनों शामिल हैं। इसके अलावा, साइबर अपराधी वायरस, मैलवेयर, अश्लील सामग्री और अन्य गैरकानूनी डेटा भेजने के लिए कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। पैसा बनाने के लिए साइबर अपराधी कई लाभ-संचालित आपराधिक कृत्यों में संलग्न होते हैं जिसमें किसी के पहचान की चोरी और पुनर्विक्रय, वित्तीय खातों तक पहुंच प्राप्त करना और धन प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना शामिल है।



साइबर अपराध की श्रेणी

- ◆ **सॉफ्टवेयर पाइरेसी:** सॉफ्टवेयर की नकल तैयार कर सस्ते दामों में बेचना साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही साथ हमारे कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं।
- ◆ **फर्जी बैंक कॉल:** इसमें अपराधी, बैंक अधिकारी जैसा बनकर किसी को भी जाली ई-मेल, मैसेज या फोन कॉल कर उनसे उनके एटीएम नंबर और पासवर्ड की जानकारी मांगते हैं या इस लिंक पर सूचना देने को कहते हैं और ऐसा नहीं करने पर उनके बैंक खाते बंद करने की चेतावनी देते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बैंक द्वारा ऐसी जानकारी कभी भी इस तरह से नहीं मांगी जाती है।
- ◆ **सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना:** बहुत से लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनैतिक अफवाह फैलाने का काम करते हैं लेकिन यूजर्स उनके इरादों समझ नहीं पाते हैं और जाने-अनजाने में ऐसे लिंक्स को शेयर करते रहते हैं। यह भी साइबर अपराध की

श्रेणी में आता है।

- ◆ **साइबर बुलिंग:** फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियाँ देना किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि तंग हो जाये, इंटरनेट पर दूसरों के सामने शर्मिंदा करना, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अक्सर बच्चे इसका शिकार होते हैं। इससे इनके सेहत पर भी असर पड़ता है।

जैसे-जैसे बैंक के उपभोक्ता मोबाइल और वेब-आधारित सेवाओं का इस्तेमाल कर नकदी रहित हो रहे हैं, ये बैंक एवं उपभोक्ताओं के लिए साइबर अपराध के अधिक जोखिम पैदा कर रहे हैं। वर्ष 2016 में ही यह बताया गया था कि पिछले दो वर्षों में 54% संगठन, साइबर अपराध से प्रभावित हुए हैं। जैसा कि हर कोई कल्पना कर सकता है, जहां तक साइबर अपराध में बैंकिंग क्षेत्र को सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक माना जाता है। साइबर अपराध और बैंकिंग इस तरह जुड़ गए हैं कि जैसे ही एक भेद्यता को संबोधित किया जाता है, दूसरा तैयार हो जाता है। जिन विविध तरीकों से उपभोक्ता तेजी से अपने पैसों का लेनदेन कर रहे हैं, अगर साइबर अपराध एवं इसके रोकथाम पर ध्यान न केंद्रित किया जाये तो कुछ विनाशकारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अपराधियों द्वारा रणनीति और तकनीक में बदलाव, बैंक ग्राहकों पर हमले, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले, बैंकों की सेवा करने वाली तृतीय-पक्ष कंपनियों पर हमले इत्यादि नवाचार करके साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर अपराधियों ने महसूस किया कि वे न केवल बैंकिंग खातों से समझौता करके, बल्कि बैंक के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाकर या भुगतान दस्तावेजों और प्रणालियों के साथ हस्तक्षेप करके पैसे चुरा सकते हैं। हमलावर नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाते हैं। दुर्भाग्य से, कई बैंकिंग प्रणाली अवयव, जैसे आंतरिक बैंकिंग सिस्टम या पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) इंटरफेस, अक्सर इंटरनेट पर उजागर होते हैं जिनको अवसरवादी हमलावरों द्वारा लक्षित किए जाने की अधिक संभावना होती है।

बैंकों के लिए शीर्ष साइबर अपराध

विगत वर्षों के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों में साइबर अपराध के हेतु रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं -

- ◆ **रैंसमवेयर:** रैंसमवेयर कई वर्षों से दुनिया भर के संगठनों के लिए एक प्रमुख सिरदर्द रहा है और जल्द ही किसी भी समय रुकने की तरह नहीं दिखता है। यह साइबर अपराध का एक तरीका है जहां फाइलों को एन्क्रिप्ट किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को बंद कर दिया जाता है, अपराधियों के साथ सिस्टम को फिर से एक्सेस करने के लिए पैसे की मांग की जाती है।

- ◆ **क्लाउड-आधारित साइबर हमले:** चूंकि अधिकांश सॉफ्टवेयर सिस्टम और डेटा क्लाउड में संग्रहीत होते हैं, साइबर अपराधियों ने इस पर कब्जा कर लिया है और परिणामस्वरूप क्लाउड-आधारित हमलों में वृद्धि बैंकिंग उद्योग के लिए सबसे प्रचलित साइबर खतरों में से एक रही है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हानिकारक उल्लंघनों से बचाने के लिए क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रूप से कॉन्फिगर किया गया है। महामारी के दौरान दूरस्थ कार्य पर निर्भरता ने भी इस प्रकार के हमले को सुभेद्यता प्रदान की है।

- ◆ **सोशल इंजीनियरिंग:** बैंकिंग और वित्त के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक सोशल इंजीनियरिंग है। लोग, अक्सर सुरक्षा श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी होते हैं। उन्हें संवेदनशील विवरण और साख देने के लिए धोखा दिया जा सकता है। यह बैंक के कर्मचारियों या उसके ग्राहकों को समान रूप से प्रभावित कर सकता है। सोशल इंजीनियरिंग कई रूप लेता है, यह फिशिंग या व्हेलिंग हमलों के माध्यम से हो सकता है या यह फर्जी चालान भेजकर हो सकता है जो एक विश्वसनीय स्रोत से होने का दावा करता है।

- ◆ **आपूर्ति श्रृंखला हमले:** साइबर अपराधियों द्वारा मेलवेयर का तेजी से वितरण, सॉफ्टवेयर विक्रेता को लक्षित करना है और फिर उत्पादों या अद्यतनों के रूप में आपूर्ति श्रृंखला में ग्राहकों और अन्य लोगों को दुर्भावनापूर्ण कोड वितरित करना है जो सतह पर वैध प्रतीत होते हैं। ये हमले वितरण प्रणाली से समझौता करते हैं और साइबर अपराधियों को आपूर्तिकर्ता के ग्राहकों के नेटवर्क में प्रवेश करने में सक्षम बनाते हैं।

साइबर अपराध के रोकथाम के उपाय

बैंक की साइबर सुरक्षा का निर्माण एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जोखिम प्रबंधन योजनाओं को जोखिम मूल्यांकन आयोजित करके और नए जोखिमों की पहचान करके लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपडेट और अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है क्योंकि नए और बेहतर संस्करण अक्सर विगत में मौजूद कमजोरियों को



संबोधित करते हैं। साइबर अपराध से लड़ने और जोखिम को कम करने के लिए देशों के भीतर एक साझा उपक्रम होना चाहिए। साइबर अपराध को रोकने के लिए इसके सैद्धांतिक व प्रायोगिक दोनों पक्षों पर समान दृष्टिकोण आवश्यक है। विस्तृत योजना का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन साइबर अपराध को क्रमशः न्यून करेगा। साइबर अपराध के रोकथाम के कतिपय चरण इस प्रकार हो सकते हैं:

1) **साइबर अपराध को संबोधित करने वाली नीतियां तैयार करना:**

किसी भी साइबर अपराध को रोकने में मदद करने वाली आंतरिक कॉर्पोरेट नीतियों को लागू करना आवश्यक है। इनमें शामिल है –

- ◆ प्रत्येक कर्मचारी के पास एक अलग उपयोगकर्ता खाता होना चाहिए और एक नीति होनी चाहिए जो हर तीन महीने में पासवर्ड बदलने को निर्धारित करती है।
- ◆ व्यवस्थापकों को कर्मचारियों को अनधिकृत सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने और स्थापित करने से प्रतिबंधित करना चाहिए।
- ◆ बैंक नीतियों को उचित अनुमोदन प्रोटोकॉल भी निर्धारित करना चाहिए।

2) **कर्मचारियों को शिक्षित करना:** मानव त्रुटि, डेटा उल्लंघनों का प्रमुख कारण है इसलिए कर्मचारियों को उनके सामने आने वाले खतरों से निपटने के लिए ज्ञान से सज्जित करना आवश्यक है। हम चाहे कर्मचारियों के प्रशिक्षण को एक 'टूल' के रूप में ना देखे लेकिन एक जानकार कर्मचारी, साइबर सुरक्षा में अपनी भूमिका को समझता है। कई प्रशिक्षण उपकरण हैं जो हम सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा प्रथाओं के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें शामिल है—

- ◆ सभी कर्मचारियों को अज्ञात स्रोतों से ई-मेल अटैचमेंट खोलने या डाउनलोड करने के खतरों से अवगत कराया जाना चाहिए।
- ◆ कर्मचारियों को संस्था के बारे में गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- ◆ बैंक के कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को हमेशा उस विक्रेता या ग्राहक के विवरण को सत्यापित करना चाहिए जिसने बिलिंग खाते में किसी भी बदलाव का अनुरोध किया है।
- ◆ नेटवर्क में किसी भी मेलवेयर या दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का पता लगाने के लिए सभी पीसी को एंटी-वायरस और एंटी-स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर के साथ स्थापित किया जाना



चाहिए।

- ◆ सभी वायरलेस नेटवर्क और उनके पासवर्ड अच्छी तरह से सुरक्षित होने चाहिए।

3) **मशीनों को नियमित रूप से सुदृढ़ रखना:** अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिये, प्रत्येक व्यवसाय व बैंकों को निम्न महत्वपूर्ण उपकरण और सेवाएं में निवेश करने पर विचार करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल है –

- ◆ **फायरवॉल :** एक फायरवॉल यकीनन सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों में से एक है। इसका काम हमारे सिस्टम में किसी भी अनधिकृत पहुंच को रोकना है। एक फायरवॉल, नेटवर्क ट्रैफिक के साथ-साथ कनेक्शन के प्रयासों की निगरानी करता है। फायरवॉल हमारे बैंकिंग व्यवसाय पर कई विद्वेषपूर्ण हमलों का पता लगाने में बहुत प्रभावी है।
- ◆ **एंटीवायरस सॉफ्टवेयर:** आमतौर पर हम फायरवॉल और एंटीवायरस शब्द को समानार्थी समझ लेते हैं लेकिन वे समान नहीं हैं। बैंकों में सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत फायरवॉल और अप-टू-डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। वर्तमान परिवेश में दोनों साइबर अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें वायरस और मालवेयर संक्रमणों के लिए सचेत करता है और कई अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करता है जैसे ई-मेल को स्कैन कर यह सुनिश्चित करना कि वे विद्वेषपूर्ण अनुलग्नकों या वेब लिंक से मुक्त हैं अथवा नहीं।
- ◆ **पीकेआई सेवाएं:** बहुत से लोग पीकेआई को सिर्फ एसएसएल या टीएलएस के साथ जोड़ते हैं। वह तकनीक जो सर्वर संचार को एन्क्रिप्ट करती है और हमारे ब्राउजर एड्रेस बार में देखे जाने वाले एचटीटीपीएस और पैडलॉक के लिए जिम्मेदार होती है। सर्वर सुरक्षा के अलावा, पीकेआई का उपयोग निम्न के लिये भी किया जा सकता है—

- i. मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण और अभिगम नियंत्रण

सक्षम करना

- ii. आज्ञाकारी, विश्वसनीय डिजिटल हस्ताक्षर बनाना
- iii. ई-मेल संचार को एन्क्रिप्ट करना और प्रेषक की पहचान को प्रमाणित करना
- iv. डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और सुरक्षा कोड

◆ **प्रबंधित जांच सेवाएं:** जैसे-जैसे साइबर अपराधी अधिक परिष्कृत होते गए हैं, और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक और सॉफ्टवेयर अधिक उन्नत हो गए हैं। बैंको के रक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली रूपों में निवेश करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा ने प्रौद्योगिकियों की निवेश में एक बदलाव देखा है जो संभावित सुरक्षा मुद्दों पर प्रतिक्रिया करने और उनका पता लगाने के लिए उन्नत सेवाओं की ओर हमले की संभावना को रोकने का प्रयास करता है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें जवाब देता है। यह पहले से ही अपने आईटी नेटवर्क पर मजबूत पैर जमाने वाले हमले को संभालने की कोशिश करने की बजाय, फैलने से पहले किसी हमले की पहचान कर, उसे खत्म करता है।

◆ **नेटवर्क सुरक्षा:** नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क और डेटा की उपयोगिता और अखंडता की सुरक्षा करने की प्रक्रिया है। यह एक नेटवर्क प्रवेश परीक्षण आयोजित करके प्राप्त किया जाता है जो हमारे नेटवर्क की कमजोरियों और सुरक्षा समस्याओं को स्कैन करता है।

◆ **प्रवेश परीक्षण:** प्रवेश परीक्षण, बैंको की सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। एक पैट परीक्षण के दौरान, साइबर सुरक्षा, पेशेवर संभावित हैकर्स और भेद्य क्षेत्रों की जांच के लिए आपराधिक हैकर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली समान तकनीकों का उपयोग करते हैं। एक पेन टेस्ट, एक तरह के हमले को अंजाम देने का प्रयास करता है जो आपराधिक हैकर्स से सामना कर सकता है जिसमें पासवर्ड क्रैकिंग और कोड इंजेक्शन से लेकर फिशिंग तक सब कुछ शामिल है।

4) **उन्नत प्रमाणीकरण तकनीकों को अपनाना:** इनमें शामिल है—

- ◆ वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए उन्नत स्तर के प्रमाणीकरण की आवश्यकता।
- ◆ बैंकों को ऐसी उन्नत तकनीकों को तैनात करना चाहिए जो वेबसाइट नेविगेशन या लेनदेन में पाए गए पैटर्न के आधार पर साइबर अपराध का पता लगा सकें। इनमें स्मार्ट

कार्ड, गोपनीय पिन, चेहरे की पहचान, फिंगर-प्रिंट सेंसर इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

5) **संयुक्त दृष्टिकोण का प्रयोग करें:** बैंकों को अपने आईटी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कई तकनीकों के संयोजन को लागू करने की आवश्यकता है। सही तकनीकों के उपयुक्त संयोजन का चयन करने से मजबूत प्रमाणीकरण, व्यवहार संबंधी धोखाधड़ी का पता लगाने और आउट-ऑफ-बैंड लेनदेन सत्यापन जैसे लाभ मिलेंगे।

6) **ग्राहक जागरूकता बढ़ाना:** इनमें शामिल किया जा सकता है—

- ◆ यह महत्वपूर्ण है कि ग्राहकों को उनके बैंक खातों से संबंधित किसी भी अनैतिक गतिविधि से अवगत कराया जाए।
- ◆ प्रत्येक बैंक को लेनदेन की वैधता की पुष्टि करने वाले ग्राहकों को अलर्ट और स्वचालित संदेश भेजना चाहिए।
- ◆ खाता विवरण मांगने वाले किसी भी स्रोत की प्रामाणिकता की जांच के लिए ग्राहकों को दिशा-निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए।

आईबीए ने कहा है कि अब जरूरी है कि सभी बैंक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों, खतरे और प्रौद्योगिकी में होने वाले बदलावों से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करें। आज के नकद- रहित बैंकिंग युग में, अपनी साइबर सुरक्षा संसाधनों को मजबूत करना बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। यदि बैंक किसी बड़े हमले से बचते हुए उपभोक्ता व्यवहार को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने वेब और मोबाइल साइबर सुरक्षा प्रथाओं को अपडेट करने की आवश्यकता होगी। बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने ग्राहकों के फंड को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखें और यह चुनौती आने वाले वर्षों में और भी कठिन हो जाएगी।

एक ठोस साइबर सुरक्षा रणनीति, हमले के विरुद्ध सबसे अच्छा बचाव है लेकिन कई संगठनों को पता नहीं है कि कहां से शुरू करना है। बैंकों को एक मजबूत साइबर सुरक्षा नीति बनानी होगी जिसमें साइबर हमलों से होने वाले खतरों का विवरण हो और उससे निपटने के तरीकों का उल्लेख हो। केंद्रीय बैंक ने कहा कि एक साइबर संकट प्रबंधन योजना का तत्काल विकास किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि बैंकिंग प्रणाली पर होने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों को देखते हुए यह आवश्यक है कि साइबर खतरों से बचने के मौजूदा रक्षात्मक उपायों को बेहतर बनाकर बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन को दुरुस्त किया जाए।

—प्रबंधक

आस्ति वसूली शाखा
अंचल कार्यालय दिल्ली—।



दीपिका दीक्षित

ग्राहक के मुख से

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों/उदारीकरण के लगभग एक दशक उपरांत भारतीय समाज में एक धारणा को बल मिलने लगा कि निजी क्षेत्र के संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहीं अधिक अच्छे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में भी उपर्युक्त धारणा बहुत तेजी से अपनी जगह बनाने लगी। मैं भी इस धारणा से प्रभावित थी परंतु मन में यह विचार हमेशा ही आता था कि लगभग एक सदी से भी पुराने ये उपक्रम क्या अपनी कमजोर नींव पर खड़े हैं। बैंकिंग का क्षेत्र लगभग शत-प्रतिशत आबादी में अपना

दखल रखता है। अतः समय के साथ मैंने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खाता होने के बाद भी निजी क्षेत्र के बैंक में खाता रखना उचित समझा। लगभग तीन माह पहले मुझे कृषि कार्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ी जिसके लिए मैंने उन दोनों बैंकों में संपर्क किया जहाँ मेरा पहले से खाता है परंतु उन दोनों बैंकों में केसीसी के लिए लंबी औपचारिकता सूची गिनाई गई। अब मुझे लगने लगा कि केसीसी बनवाने में बैंक को कोई फायदा नहीं है जबकि मेरा सिबिल स्कोर भी बैंक नियमानुसार सारी अहर्ताएं पूरी करता है।

इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक सामाजिक कार्यक्रम में पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा महाराजपुर (मध्यप्रदेश) के प्रभारी श्री सौरभ सिंघई से मुलाकात हुई। जब मैंने उन्हें केसीसी के विषय में बताया तो उन्होंने समस्त दस्तावेजों सहित अगले दिन ही बैंक शाखा में उपस्थित होने को कहा। अगले कार्यदिवस में मैं और मेरे पति श्री दीपक दीक्षित नियत समय में शाखा पहुंचे जहाँ पर शाखा प्रबंधक श्री सिंघई ने मेरे समस्त दस्तावेजों की जांच कर केसीसी उपलब्ध कराने की बात कही। कुछ दिन बाद ही बैंक शाखा से फोन आने पर हम लोग शाखा पहुंचे जहाँ पर एक बैठक (सीटिंग) में ही सारी अनिवार्यताएं शाखा प्रबंधक महोदय एवं स्टाफ द्वारा पूर्ण कर ली गई। साथ ही मेरा एवं मेरी पति का बचत खाता भी खोला गया। इस सभी औपचारिकताओं के पश्चात अगले ही दिन शाखा से फोन करके बताया गया कि आपके केसीसी खाते में राशि क्रेडिट कर दी गई है।

मैं, पीएसबी की इतनी त्वरित कार्यवाही से अभिभूत हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि बैंक में इतनी अच्छी सेवा प्रदान की जाती है। मैं शाखा प्रबंधक एवं शाखा के समस्त स्टाफ सदस्यों की आभारी हूँ और इस लेख के माध्यम से उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरा यह विचार कि "निजी क्षेत्र के संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कहीं अधिक अच्छे हैं" को अपनी सेवा भावना से बदल दिया। कोई संस्था तकनीकी रूप से कितने भी संपन्न हो लेकिन उनके अधिकारियों में यदि सेवा-भावना नहीं है तो उनका प्रयास शायद ही सफल हो पाएगा।

मुझे पता नहीं कि कृषकों को केसीसी प्रदान करके बैंक को कितना आर्थिक लाभ होता है लेकिन मेरी यह धारणा प्रबल हो गई है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखाएं अपने अन्य ग्राहकों को भी इसी तरह निःस्वार्थ और त्वरित सेवाएं प्रदान करती होंगी। अब मैं यह कह सकती हूँ कि निःसंदेह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही सर्वश्रेष्ठ हैं जो आज भी भारत के सामाजिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

- दीपिका दीक्षित (कृषक)

महाराजपुर, जिला : जबलपुर (म.प्र.)

सेवानिवृत्ति



31 दिसंबर, 2022 को बैंक के महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी, बैंकिंग सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। महाप्रबंधक के रूप में श्री सेठी जी के पास राजभाषा विभाग के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास विभाग, जनसंपर्क विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सुरक्षा विभाग तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का प्रभार रहा। इससे पूर्व आप अंचल कार्यालय लखनऊ तथा अंचल कार्यालय कोलकाता में आंचलिक प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे।

अपने 38 साल के बैंकिंग कैरियर में श्री सेठी जी ने विभिन्न पदों व क्षेत्रों में कार्य किया। वर्ष 1984 में लिपिक पद से अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत करने के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड तथा दिल्ली में कार्य करने का अवसर मिला। श्री कामेश सेठी जी क्रमशः पदोन्नत होते हुए वर्ष 2020 में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हुए। आपने लगभग दो वर्षों तक बैंक की हिंदी तिमाही पत्रिका "राजभाषा अंकुर" तथा गृह-पत्रिका "नवोदय" का सफल संपादन किया। संपादक बनने से पूर्व भी आप लेखन कार्यों से भी जुड़े रहे और बैंक की पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। इसके इतर आप बैंक के रंगमंच कार्यक्रमों और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल रहे।

31 दिसंबर, 2022 को अधिवर्षिता आयु पूरी होने पर श्री सेठी जी को सेवानिवृत्ति दी गई। उनके सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशक (केवीआर), कार्यकारी निदेशक (राम) सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में श्री कामेश सेठी जी के परिवार के सदस्य को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। बैंक आपके स्वस्थ, सुखद तथा मंगलमय सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता है।

शुभकामनाओं सहित!
—पीएसबी परिवार



भीम सिंह
उप निदेशक (राजभाषा)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
"जीवन दीप"
१०, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-११०००१

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
"JEEVAN DEEP"
10, PARLIAMENT STREET,
NEW DELHI-110 001

दिनांक Dated the 29-11-2022

अ.शा. पत्र संख्या 11011/3.नि./2022-हिंदी

परम आदरणीय श्री स्वरूप कुमार साहा जी,

मैं सहर्ष सूचित करना चाहता हूँ कि लगभग 39 वर्ष की सरकारी सेवा के उपरांत अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवम्बर, 2022 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ।

वित्तीय सेवाएं विभाग में मेरे 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति तथा वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा समय-समय पर पंजाब एण्ड सिंध बैंक के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण प्रधान कार्यालयों और संबंधित कार्यालयों के समन्वय और सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों के समय पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा किए गए उत्कृष्ट समन्वय की संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों ने भी प्रशंसा की।

मैं इस अवसर पर विशेष रूप से आपको तथा श्री कामेश सेठी जी, महाप्रबंधक, श्री निखिल शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) तथा अन्य राजभाषा अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने राजभाषा निरीक्षणों के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सेवाएं विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक आने वाले दिनों में व्यापार के सभी पैमानों के साथ-साथ राजभाषा के कार्यान्वयन में भी सफलता की बुलंदियों को छुएगा। मैं एक बार फिर से बैंक के उच्च प्रबंधन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ तथा सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं यह भी कामना करता हूँ कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक अपने कारोबार में निरन्तर वृद्धि करते हुए राजभाषा के कार्यान्वयन में भी अग्रणी रहे। मैं आश्वस्त करता हूँ कि यदि भविष्य में भी पंजाब एण्ड सिंध बैंक को मेरी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो मुझे उसमें सहयोग करने में प्रसन्नता होगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

आपका शुभेच्छु

(भीम सिंह)

श्री स्वरूप कुमार साहा,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, दिल्ली

दिल्ली बैंक नराकास में बैंक



उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2022 के लिए दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड पुरस्कार तथा ई-पत्रिका प्रतियोगिता में बैंक को पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन में प्रधान कार्यालय को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ जबकि बैंक की तिमाही ई-पत्रिका 'राजदीप' को अंतर बैंक ई-पत्रिका प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही दिल्ली बैंक नराकास की छमाही पत्रिका 'बैंक भारती' के 26वें तथा 27वें अंक में प्रकाशित रचनाओं के लिए बैंकिंग विषयक लेख की श्रेणी में श्री नागमणि, वरिष्ठ प्रबंधक को प्रथम पुरस्कार मिला है।

पुरस्कारों का वितरण 22 दिसंबर, 2022 को आयोजित नराकास की 57वीं छमाही बैठक में किया गया। बैठक में महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री कामेश सेठी तथा वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री निखिल शर्मा ने बैंक का प्रतिनिधित्व किया।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति का दौरा कार्यक्रम

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने 10 अक्टूबर, 2022 को बैंक की भावनगर शाखा का राजभाषाई निरीक्षण किया। निरीक्षण कार्यक्रम में बैंक की ओर से शाखा प्रबंधक श्री पृथ्वी राज मीणा, आंचलिक प्रबंधक गाँधीनगर श्री संजीव कुमार गुप्ता, अंचल कार्यालय गाँधीनगर में पदस्थ नामित राजभाषा अधिकारी सुश्री प्रज्ञा सिंह, महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री कामेश सेठी तथा प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग में पदस्थ वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री निखिल शर्मा उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान माननीय सदस्यों ने शाखा में राजभाषा कार्यान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की तथापि अपेक्षाकृत बेहतर परिणामों के लिए बैंक का मार्गदर्शन किया और यथोचित निर्देश दिए।







पवन कुमार जैन

चैला-चिमटा और सवाल - व्यंग्य

बचपन में मनीष कुमार ही हमारा इकलौता और पक्कम-पक्का दोस्त हुआ करता था। हमारे उसके बीच में कोई एक भी आदत नहीं मिलती थी, वह घनघोर पढ़ाकू टाइप का था। वह अपने सिर में ढेर सारा कड़ुआ तेल चुपड़े रहता था, ऐसा लगता था कि तेल की फैंट्री से निकलकर आया हो। हम लोग स्कूल/ कॉलेज तक तो एक साथ ही जाते थे मगर क्लास में घुसने के बाद अलग-अलग हो जाते थे। पढ़ाई को लेकर हमारे विचार मुख्तलिफ थे, मैं सवालों पर विश्वास करता था और वह जवाबों पर। इसीलिए वह सबसे आगे की बेंच पर बैठता था और मैं सबसे पीछे। हम दोनों लोग पढ़ाई को छोड़कर दूसरी सारी बातें किया करते थे। गुरुजी के हर सवाल का जवाब वह तुरंत दे देता था परंतु मैंने अम्मा की नसीहत को हमेशा गाँठ बांधकर रखा कि अपने से बड़े लोगों को कभी जवाब नहीं देना है। गुरुजी जब भी मुझसे सवाल पूछने की मुद्रा में आते मेरा हाथ गुद्दी पर अपने आप पहुँच जाता था, ऐसा लगता था कि जवाब गुद्दी में कहीं छिपा हुआ है। आज तक हमारी समझ में यह नहीं आया कि गुरुजी जब कोई सवाल पूछते हैं तो हाथ गुद्दी पर ही क्यों जाता है, आप लोगों को अगर पता चले तो जरूर बताना। सवाल का जवाब न देने पर गुरुजी की भृकुटियाँ तन जातीं और वे हमें पुरानी रुई की तरह कस के धुन देते थे। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि जब उनके हाथ में खुजली होती थी तभी वह मुझसे सवाल पूछते थे, महीने में एक-दो बार तो वह सवाल पूछ ही लेते थे। शुरू-शुरू में तो काफी बेइज्जती महसूस हुई मगर बाद में यह रूटीन बन गया था।

दोस्तों, एक बात और है जो मुझे काफी परेशान करती रहती है, वह यह कि पढ़ाकू टाइप के लोगों के नाम काफी अच्छे-अच्छे क्यों होते हैं। उनके नाम श्यामलाल या छुट्टन टाइप के क्यों नहीं रखे जाते। यह सवाल मैंने एक बार अम्मा को काफी कान्फीडेंस में लेकर बड़ी संजीदगी के साथ किया था। वह मेरे सवालों की बारिश से वैसे ही



भुनी रहती थीं, उन्होंने चूल्हे से चौला (सूखी जलावन वाली लकड़ी) उठाकर मेरी पीठ का भरपूर आदर-सत्कार किया था ... अब किया तो किया।

एक दिन मैंने उन्हें बताया कि अम्मा मुझे बहुत सारे सवाल परेशान करते रहिते हैं, रात भर सोने नहीं देते, उन सवालों के अजीबोगरीब सपने आते रहते हैं, इसके पहिले कि मैं सवालों पर कोई सवाल दाग पाता, अम्मा ने फिर चौले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया मगर मैं आने वाली आपदा को भाँपते हुए वहाँ से चुपचाप खिसक लिया। दोस्तों चौला और चिमटा अम्मा का अमोघ-अस्त्र था जिसने मेरे कैरियर को ऊँचाइयों पर ले जाने में भरपूर मदद की। आप लोग भी यह नुस्खा आजमा सकते हैं (हालाँकि इसमें पर्याप्त जोखिम है, कृपया अपनी गारंटी पर हमारी सलाह माँनें)।

इधर हम पर चौलों और चिमटों की बारिश होती रही और उधर

अपना मनीष किताबों को चाट-चाटकर डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद उसने एक स्लम एरिया में अपनी क्लीनिक खोल ली, वहाँ पर मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। मनीष के दृष्टिकोण से यह हेल्दी एरिया था। इंसान को मरीज बनाने की तमाम सहूलियतें वहाँ पर बहुतायत से उपलब्ध थीं, मरीजों की लंबी कतारों को देखकर वह खुश होता रहता था। मुझे लगता है वहाँ के लोग खाना कम और दवाइयाँ ज्यादा खाते थे। क्लीनिक खोलते ही वह धूप-अगरबत्ती जलाकर भगवान से मरीजों को भेजने की प्रार्थना करता था। यह दुनिया भी अजीब है भाई, डॉक्टर चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ें ताकि उनकी डॉक्टरी खूब चले। वकील सोचता है कि लोग आपस में झगड़ा करें ताकि वे उनका केस लड़ें, लोगों में जितना ज्यादा झगड़ा होगा, उनकी उतनी ज्यादा वकालत चलेगी। इसी तरह पुलिस वाले चाहते हैं कि उनके इलाके में खूब क्राइम बढे। यहाँ तक कि कफन बेचने वाला भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरें, महामारी आ जाए... हर चलते-फिरते इंसान को वह लाश की शकल में देखना चाहता है ताकि वह कफन बेचकर मुनाफा कमा सके। मुहल्ले में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वह दोस्तों-रिश्तेदारों से पता करता रहता है कि यह लाश कब बनेगा।

हर कोई अपने मुनाफे और फायदे के बारे में फिक्रमंद है मगर दोस्तों समाज के एक वर्ग को हम हमेशा भूल जाते हैं, वे हमारे जेहन में ही नहीं आते जो हम लोगों के लिए, हमारे परिवार और बच्चों के लिए हमेशा दुआएँ करते हैं, इन्हें हम ट्रॉसजेंडर या छक्के कहते हैं। हालाँकि समाज में उन्हें उपहास और मजाक का ही पात्र समझा जाता है फिर भी वे हमेशा हमारी सलामती की दुआएँ करते

हैं, हमारी बलाएँ वे अपने सिर ले लेते हैं मगर देखो हमने कभी उनके लिए ताली या थाली नहीं बजाई। यहाँ तक कि उन्हें समाज में कोई हैसियत भी नहीं दी। सरकार और संविधान ने भी उन्हें किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया। आप किसी भी सरकारी/गैर सरकारी फार्म को देखें उसमें महिला/पुरुष का कॉलम तो होता है परन्तु ट्रॉसजेंडर्स का कोई अलग से कॉलम नहीं होता। सीधी सी बात है कि उन्हें समाज से अलग समझा जाता है जबकि इस तरह का होने में उनकी अपनी कोई च्वाइस नहीं होती। वे हमारी खुशियों में हमसे ज्यादा खुश होते हैं और नाच-गाकर हमें दुआएँ देते हैं। देखा जाए तो समाज में खुशियाँ बाँटने वाले ये लोग भी सोशल वैरियर्स ही हैं, हमें इन लोगों का भी ताली/थाली बजाकर सम्मान करना चाहिए। उन्हें गले लगाना चाहिए क्योंकि आज तक इन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी भी अपराध में इनका नाम नहीं आता। यह सारी बातें हमारे जेहन में काफी दिनों से उमड़-धुमड़कर गैस बना रही थीं इसलिए मैं यह सवाल लेकर सीधे अम्मा के पास गया और कहा कि अम्मा एक सवाल बहुत दिनों से मुझे परेशान किए हुए है। अम्मा ने सवालियों के तूफान के आने से पहले ही उससे निपटने के लिए चिमटे की तरफ हाथ बढ़ाया मगर आज चिमटे के प्रहार को झेलने का बिल्कुल मूड नहीं था इसलिए मैंने अम्मा को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा और अपने सवालियों की सबील उठाए वहाँ से खिसक लिया। अलबत्ता आप लोगों से गुजारिश है कि यह सवाल अपने आसपास उठाते रहें। आप लोगों को तो चैले या चिमटे का भी कोई डर नहीं है।

—सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रतिक्रिया

हर्ष का विषय है कि प्रधान कार्यालय द्वारा "राजभाषा अंकुर" का निरंतर सफल प्रकाशन किया जा रहा है। किसी भी संगठन में पत्रिका का प्रकाशन संगठन के कर्मियों को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को उभारने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है जो राजभाषा संबंधी प्रचार को गति प्रदान करता है। हिंदी एक उदार भाषा है जिसने अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को सहजता से अपनाया है, हिंदी की प्रवाहमयता उसे जीवंत बनाती है। तेजी से बदल रही सूचना प्रौद्योगिकी ने भाषाओं को सीखने और उनके प्रयोग को आसान बना दिया है। अब आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम सब इनके माध्यम से अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं।

मैं "राजभाषा अंकुर" के प्रत्येक अंक को अवश्य पढ़ता हूँ। इस पत्रिका की सारी सामग्री अति मनमोहक है। सितंबर 2022 के अंक में प्रकाशित "अब और देर नहीं" तथा "हरित वित्त" लेख अत्यंत प्रवाहमय व ज्ञानवर्धक रहे एवं पत्रिका के "काव्य-मंजूषा" ने तो पत्रिका में गागर में सागर भरने का काम किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक में प्रेरणा और प्रोत्साहन से राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और उसके प्रचार-प्रसार हेतु इस पत्रिका का योगदान अवर्णनीय है।

—पवन कुमार भाटिया
आंचलिक प्रबंधक, बठिंडा

काव्य-मंजूषा

इंसान बन गया

जहां पैदा हुआ
वो धर्म बन गया।
जो करने को कहा गया
वो कर्म बन गया।।

जो किताबो में पढ़ा
वो जहन बन गया।
जो जिंदगी ने सिखाया
वो सबक बन गया।।

जहां कुछ पैसे मिले
वो रोजगार बन गया।
जिसने निभाया साथ
वो यार बन गया।।

दो शब्द उल्फत के बोले जिसने
वो प्यार बन गया।
खुद ही करके इजहार
आज वो अनजान बन गया।।

आधी उम्र गुजार कर
सच्चा झूठा पहचान कर।
दस्तूर दुनिया के जानकर
मैं बे एहसास इंसान बन गया।।



अतुल कुमार बठला
शाखा चुन्नी कलाँ
चंडीगढ़ अंचल

बाढ़ का पानी

नदी का पानी
अब खतरे के निशान से
नीचे उतरने लगा था
बांध तोड़कर नदी का पानी
जो भटक बस्ती में आ गया था
वह वापस नदी की तरफ लौटने लगा था
पानी के बीच बसे कुछ घर
टापू से बाहर निकल
जमीन पर आ गए थे
चारो तरह शांति ही शांति थी
मेढक के टर्-टर्
और झींगुर के झनक के बीच
कीचड़ में पड़े पांव के निशान
इस बात की गवाही दे रहा था कि
इसके भीतर जिंदगी बची है
अन्यथा इस बाढ़ ने
घर, आंगन, दहलीज और रसोई
सभी को लीप गया था
दूर किसी घर से
आते धुएं के निशान ने
मन में इस आशा को जन्म दिया कि
सब कुछ मिट्टी में मिलकर
मिट्टी बनने के बाद भी
कुछ जिंदगियां अब भी स्वास ले रही
उनकी जिजीविषा
बाढ़ की विभीषिका से बढ़कर है
शायद इसलिए
प्रत्येक वर्ष
बाढ़ का दंश झेलने के बाद भी
फैले पंक में
जीवन के फूल फिर से खिल जाते हैं
और जीवन फिर से चलने लगती है



बिभाष कुमार
प्रबंधक (राजभाषा)

मेरी माँ

दूध सी धवल, लंबे घने बाल
मधुर कंठ, मीठी बोली
मधुर तान पर भजनों से समा बांधती
सौंदर्य की पराकाष्ठा थी मेरी माँ

परमात्मा की सेवा करती, तरह-तरह के
भोग लगाती
नृत्य से लुभाती, ढोलक पर थाप देती
मधुर तान पर भजनों से समा बांधती
भक्ति की देवी सी थी मेरी माँ!

डॉट कर फिर लाड़ लड़ाती, अनुशासन
में हमें ढालती
स्त्री शिक्षा की पैरवी करती
हमें जीवन की हर मुश्किल में संभालती
वात्सल्य की देवी सी थी मेरी माँ!

तरह-तरह के व्यंजन बनाती
घर आए सभी को भोजन खिलाती
थोड़े में भी बरकत रहती
अन्नपूर्णा सी थी मेरी माँ!

बाऊजी की मेमसाहब, हमारी मम्मी
किसी की चाची, किसी की बुआ
किसी की मामी, किसी की मौसी
सबको रिश्तों में पिरोती, परिवार की
सूत्रधार थी मेरी माँ!



डॉ. नीरू पाठक
सेवानिवृत्त प्रबंधक

जिंदगी में तपिश कितनी भी हो

जिंदगी में तपिश कितनी भी हो
कभी हताश मत होना,
क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो
समंदर कभी सूखा नहीं करते।
जो हो गया उसे सोचा नहीं करते
जो मिल गया उसे खोया नहीं करते,
हासिल उन्हें ही होती है सफलता
जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते।

मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है
हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है,
डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में
लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है।

मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगो के हिस्से में
ही आती हैं
क्योंकि वे ही लोग उसे बेहतरीन तरीके से
अंजाम देने की ताकत रखते हैं,
बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों
लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों
का बहाव बन जाता है,
वैसे ही छोटे-छोटे लगातार प्रयास भी
जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।



अशोक सिन्हा
आंचलिक कार्यालय बरेली

खपरैल का घर

वो भी क्या दिन थे,
जब खपरैल के घर में रहते थे।
ना कूलर, ना पंखा, ना एसी,
फिर भी प्रकृति की ठंडी हवा खाते थे।

जब उस खपरैल के घर की छत पर,
बन्दर, बिल्ली एवं पक्षी सैर पर आते थे।
सारे परिवार के सदस्यों की धड़कन बढ़ाते थे
अपनी परस्पर लड़ाई एवं उछल कूद से।
पूरे घर की छत को अस्त-व्यस्त कर जाते थे,
उनकी इस परस्पर लड़ाई एवं अठखेलियों का दर्द।
सारे परिवार को बारिश में महसूस कराते थे,
वर्षा के मौसम की रातों में, पूरा परिवार।
जहां पानी नहीं टपकता, सारी रात जागकर बिताते थे।

ना कहीं मच्छर होते, नालियों में नियमित चूना डलता था।
परन्तु स्वच्छता का पूरा ध्यान देते थे,
परिवार के सभी लोग उस अस्त-व्यस्त घर में,
जिस जगह स्थान मिले, रात गुजारते थे।
स्वच्छ पानी पीने एवं नहाने के लिए,

सरकारी नलों से ढोकर लाते थे।
इसी प्रक्रिया को बार-बार करने से,
अपनी शारीरिक पुष्टता का बोझ कराते थे।

पतंगबाजी, कंचे एवं गुल्ली जंडा खेलकर,
अपनी योग्यता एवं गुणों को दर्शाते थे।
परिवार में परस्पर असीम प्यार एवं स्नेह से,
भारी से भरी दुखों को दूर भगाते थे।
ना स्कूल का भारी बस्ता ना पढ़ाई की चिन्ता,
ना ही कोई पढ़ाई के डर का एहसास कराते थे।
होमवर्क एवं स्कूल के कार्य ना करने पर,
अध्यापक अथवा माता-पिता भी नहीं डराते थे।

सोचता हूँ उन दिनों की पुनरावृत्ति हो जाये,
फिर से मेरे चेहरे पर बचपन की हसी खिल जाये।
मुमकिन हो भगवान मेरी भावनाओं पर तरस खाये,
मेरी वेदना सुनकर मुझे दोबारा वहीं दिन दिखाये।
आधुनिक सुविधाओं को छोड़कर फिर खपरैल के घर दिलायें,
बचपन की आजादी एवं अथाह प्रेम में सब फिर बस जायें।



मनजीत सिंह मलहौत्रा
सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक



हिंदी कार्यशाला



अंचल कार्यालय गुरुग्राम



अंचल कार्यालय होशियारपुर



अंचल कार्यालय मुंबई



अंचल कार्यालय नोएडा



अंचल कार्यालय पंचकूला



सहभागी

हिंदी कार्यशाला



अंचल कार्यालय बरेली



अंचल कार्यालय गुरदासपुर



अंचल कार्यालय भोपाल



अंचल कार्यालय चेन्नई



अंचल कार्यालय जयपुर



एसटीसी रोहिणी-दिल्ली



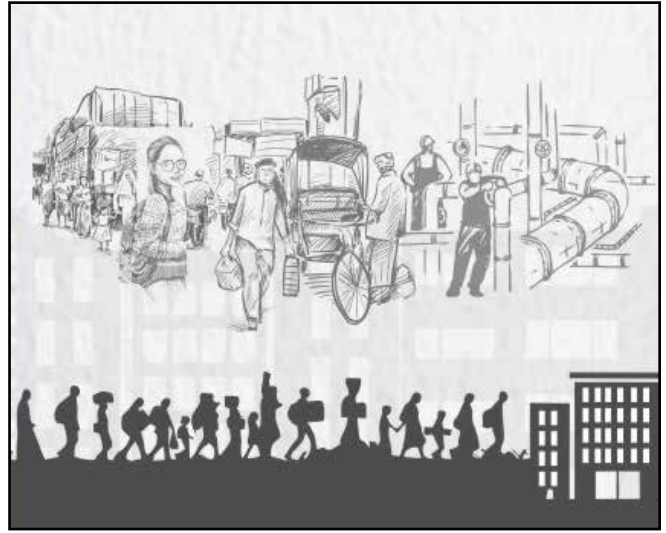
अंकुर सिन्हा

प्रधानमंत्री आवास योजना - तब से अब तक

प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री "श्री नरेंद्र मोदी जी" के द्वारा 25 जून 2015 को देश के भूमिहीन गरीब परिवारों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। योजना का लक्ष्य था कि 2022 तक देश के हर एक गरीब परिवार को अपना स्वयं का आवास मिल सके जिसकी संख्या लगभग 2 करोड़ थी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अपने 2020-21 के बजट को पेश करते हुए कहा था कि योजना के पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान सरकार बनाकर देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक जनकल्याणकारी योजना है। भारत सरकार योजना के तहत शहरों और ग्रामीण में रहने वाले गरीब लोगों के लिए पक्के और सुविधायुक्त घरों का निर्माण करवा रही है। सरकार द्वारा बने इन घरों में रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, शौचालय आदि की सुविधाएँ दी जा रही हैं। मौजूदा सरकार ने योजना के तहत ₹7.55 लाख करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है। भारत सरकार के अनुसार इस साल 20 लाख घरों के निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा जिसमें से 18 लाख घर झुग्गी और झोपड़ी वाले स्थानों पर और 2 लाख घर शहरों के गरीब इलाकों में नए और पक्के मकान बनवाए जाएंगे।

वित्तीय पहलू

योजना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खर्च योगदान धनराशि का अनुपात 75:25 रखा गया है लेकिन देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ केंद्र सरकार के खर्च राशि का अनुपात 90:10 के बीच रखा गया है एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। योजना के तहत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चार हजार से अधिक शहरों को योजना में शामिल किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को निम्नलिखित तीन चरणों में विभाजित किया है:



- ◆ आवास योजना के प्रथम चरण की शुरुआत अप्रैल, 2015 से की गई जिसके तहत केंद्र सरकार ने देश के 100 से भी अधिक शहरों में घरों का निर्माण करवाया गया। योजना का प्रथम चरण मार्च, 2017 में जाकर समाप्त हुआ।
- ◆ आवास योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत अप्रैल, 2017 से की गई जिसके तहत केंद्र सरकार ने देश के 200 से भी अधिक शहरों में घरों का निर्माण करवाया गया। योजना का द्वितीय चरण मार्च, 2019 में जाकर समाप्त हुआ।
- ◆ आवास योजना के तृतीय चरण की शुरुआत अप्रैल, 2019 से की गई जिसके तहत केंद्र सरकार योजना के अनुसार बाकी बचे शहरों में घरों का निर्माण करवा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में घर के निर्माण हेतु ऋण के लिए भी आवेदन करने की सुविधा है। सरकार, योजना के तहत घर के निर्माण के लिए ₹6 लाख से लेकर ₹12 लाख से भी अधिक का ऋण प्रदान कराती है जिस पर आपको 3% से लेकर

6.5% तक प्रतिवर्ष ब्याज-दर के अनुसार चुकौती करना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार केंद्र सरकार ने बीपीएल राशन कार्डधारकों को घर के निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि को ₹45 हजार से बढ़ाकर अब ₹70 हजार कर दिया है

पीएमएवाई की विशेषताएं

- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि योजना के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली अनुदान राशि केंद्र सरकार के द्वारा बैंकिंग ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है जिससे योजना में भ्रष्टाचार होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। योजना के अनुसार अनुदान राशि, अलग-अलग आय वर्ग के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
- ◆ योजना के अनुसार बनने वाले मकानों का आकार का क्षेत्रफल पहले 20 वर्ग मीटर (लगभग 215 वर्ग फुट) तय था जिसको केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर (लगभग 270 वर्ग फुट) कर दिया गया है।
- ◆ केंद्र सरकार ने अपनी इस आवास योजना के साथ भारत के स्वच्छता अभियान को भी जोड़ा है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार योजना के लाभार्थी को शौचालय निर्माण हेतु ₹12 हजार की धनराशि अलग से प्रदान करती है।
- ◆ योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्डधारकों को ₹70 हजार तक का लोन दिया जाता है जिस पर लोन प्राप्त करने वाले बीपीएल कार्डधारक को चुकौती के लिए कोई ब्याज नहीं देना होता है अर्थात् उधारकर्ता को सिर्फ मूल धनराशि चुकानी होती है। यह पूरा ऋण ब्याज रहित होता है।

योजना के अनुसार लोन को तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है -निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) एवं उच्च आय वर्ग (एचआईजी)।

प्रधानमंत्री आवास योजना को मुख्यतः चार अन्य योजनाओं में विभाजित किया गया है जिनके नाम इस प्रकार से हैं

आईएसएसआर: इन-सीटू स्लम पुनर्विकास	एचपी: पार्टनरशिप में किफायती आवास
सीएलएसएस: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना	बीएलसी: लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण या संवर्धन



पीएमएवाई के लाभार्थी हेतु पात्रता

योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित पत्राताओं को पूर्ण करना होगा:

- ◆ आवेदनकर्ता को भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- ◆ आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- ◆ आवेदनकर्ता के स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई संपत्ति या घर नहीं होना चाहिए।
- ◆ आवेदनकर्ता यदि केंद्र और राज्य की किसी अन्य आवास योजना का लाभार्थी है तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र है।
- ◆ आवेदनकर्ता की वार्षिक आय ₹6 लाख से लेकर ₹8 लाख तक के बीच होनी चाहिए।

पीएमएवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए -

- ◆ आवेदनकर्ता का आधारकार्ड आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)



- ◆ आवेदक का पता प्रमाण (यथा निर्धारित)
- ◆ आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
- ◆ देश के किसी भी बैंक में अपने नाम से एक बैंक खाता
- ◆ आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- ◆ बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति
- ◆ आवेदनकर्ता का सक्रिय मोबाइल नंबर

पीएमएवाई की उपलब्धियाँ

अगर बात करें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की प्रगति एवं उपलब्धियों के बारे में तो उनसे संबंधित कुछ आंकड़े न सिर्फ चौकानेवाले ही हैं बल्कि अत्यंत उत्साहजनक हैं, इनका विवरण निम्न है :

- ◆ अभी तक 122.69 लाख मकान स्वीकृत हुए हैं, वहीं 106.6 लाख मकान ग्राउंडेड हुए हैं। साथ ही 65.50 लाख मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुके हैं।
- ◆ अगर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता की तो अब तक ₹129597 करोड़ की सहायता प्राप्त हो चुकी है साथ ही ₹8.31 लाख करोड़ का कुल निवेश भी हुआ है।

वहीं अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो इनकी उपलब्धि भी उत्साहजनक है जिसमें अभी तक कुल 2.74 करोड़ मकान पंजीकृत हुए हैं। 2.69 करोड़ मकान जियो टैगिंग हुए हैं। 2.49 करोड़ मकानों को स्वीकृति प्रदान हुई है एवं 2.08 करोड़ मकान पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल ₹22841.88 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी घरों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करता है। योजना के लाभार्थी मनरेगा से 90/95 श्रम दिवस के अकुशल श्रम का भी हकदार है। शौचालय के निर्माण के लिए एसबीएम-जी को आवास योजना से जोड़ने के माध्यम से भी मदद ली जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत नल से पेयजल, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन आदि भी मिल सकता है।

इस कार्यक्रम को ई-गवर्नेंस समाधान आवास सॉफ्ट और आवास ऐप के माध्यम से लागू किया जा रहा है और इन्हीं ऐप के जरिए



इनकी निगरानी भी की जा रही है। आवास सॉफ्ट ऐप इस योजना के कार्यान्वयन पहलुओं से संबंधित कई आंकड़ों की डाटा रखने और निगरानी के लिए बेहतर साधन के रूप में काम करता है। इन आंकड़ों में भौतिक प्रगति (पंजीकरण, स्वीकृतियाँ, मकान निर्माण पूरा करना और किशतों का जारी होना इत्यादि), वित्तीय प्रगति, अन्य योजनाओं के साथ मिलान की स्थिति आदि शामिल हैं।

पीएमएवाई के अंतर्गत ऋण देने वाली संस्थाएं

- ◆ आवास और शहरी विकास निगम (हुडको)
- ◆ राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
- ◆ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही भारत सरकार के कई अन्य योजनाओं को भी एकीकृत किया गया जिससे कि सभी योजनाओं में अनूठा समन्वय बन सके, यह योजनाएं हैं :

- ◆ कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)
- ◆ "रेरा" के तहत पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंट
- ◆ दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- ◆ जल शक्ति अभियान
- ◆ पीएम स्वनिधि ऋण
- ◆ राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय)
- ◆ शहरी परिवहन

साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आसान सुगम एवं सुरक्षित बनाया गया है तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिससे ग्राहक अपने सभी प्रकार के आवेदनों की जानकारी एवं उनकी स्थिति का पता लगा सकेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के विविध आयाम:

- ◆ **किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एचआरएलसी):** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत एक उप-योजना किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स शुरू की गई है। यह शहरी प्रवासियों/ औद्योगिक क्षेत्र में गरीबों के साथ-साथ अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में उनके कार्यस्थल के करीब सम्मानजनक किफायती किराए के आवास तक पहुंच प्राप्त करने में सुगमता प्रदान करेगा।
- ◆ **वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती: भारत :** शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - भारत (जीएचटीसी-इंडिया) की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र के लिए दुनिया भर से नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों की एक टोकरी की पहचान करना और उसे मुख्यधारा में लाना है जो टिकारू और पर्यावरण अनुकूल हैं।
- ◆ **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएपी):** वेब आधारित निगरानी प्रणाली, सीएलएसएस आवास पोर्टल (सीएलएपी) एक सामान्य मंच है जहां सभी हितधारक अर्थात् एमओएचयूए, केंद्रीय नोडल एजेंसियां, प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थान, लाभार्थी और नागरिक वास्तविक समय के वातावरण में एकीकृत होते हैं। पोर्टल लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी की स्थिति पर नजर रखने के साथ-साथ आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है। सीएलएसएस ट्रैकर को पीएमएवाई (यू) मोबाइल ऐप और उमंग प्लेटफॉर्म में भी शामिल किया गया है।
- ◆ **मुख्य सॉफ्टवेयर मॉड्यूल:** भूमिहीन मॉड्यूल, ई-टिकटिंग प्रणाली, आधार आधारित भुगतान प्रणाली, ई-लनिंग प्लेटफॉर्म एवं अन्य प्रकार के नए सॉफ्टवेयर एवं तकनीक का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री आवास योजना के हितधारकों के क्षमता निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की चुनौतियां

उपलब्धियों के साथ इस योजना के समक्ष कतिपय चुनौतियाँ भी हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। इससे हम भविष्य में और भी विकासशील मॉडल तैयार कर सकते हैं। चुनौतियां इस प्रकार हैं :

- ◆ जमीन की कमी
- ◆ सदियों पुरानी प्रौद्योगिकियां
- ◆ भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे की कमी



- ◆ कुशल कार्यबल की कमी
- ◆ विलंबित परियोजना अनुमोदन
- ◆ असंरचित संपत्ति अभिलेख
- ◆ कच्चे माल और श्रम की बढ़ती लागत
- ◆ असंगठित कार्य क्षेत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना को समाज के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचाने हेतु इस योजना के मूल बिंदु को ध्यान में रखना होगा तथा समाज में मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस योजना में नई तकनीकी का उपयोग करके और मानवीय एवं वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाकर इसे और भी सुगम एवं सुरक्षित बना सकते हैं जिससे कि यह अधिक से अधिक लोगों के लिए लाभदायक हो सके। वहीं बात करें इस नवीन एवं उपयोगी योजना की तो इसका भविष्य भी बहुत ही सुगम एवं सुरक्षित है। आने वाले समय में यह सभी भारतीयों को पक्के मकान एवं बुनियादी ढांचे के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगा जैसे कि पेयजल की सुविधा, बिजली की सुविधा, अच्छे राजमार्ग, परिवहन की सुविधा, उन्नत किस्म के विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल और साथ ही साथ रोजगार के अवसर। और यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ना सिर्फ एक योजना है बल्कि संविधान के प्रारूप में दिए गए कुछ मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी सूचक है।

—एकल खिड़की परिचालक
शाखा न्यू आगरा, गुरुग्राम अंचल

अंचल कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022



अंचल कार्यालय अमृतसर



अंचल कार्यालय भोपाल



अंचल कार्यालय बठिंडा



अंचल कार्यालय मुंबई



अंचल कार्यालय फरीदकोट



अंचल कार्यालय गाँधीनगर

अंचल कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022



अंचल कार्यालय होशियारपुर



अंचल कार्यालय दिल्ली-1



अंचल कार्यालय कोलकाता



अंचल कार्यालय बरेली



अंचल कार्यालय नोएडा



अंचल कार्यालय गुरुग्राम



राकेश चन्द्र नारायण

मेरी खजुराहो यात्रा

महापंडित राहुल सांकृत्यायन और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' का घुमक्कड़ी से जन्म का नाता था। सांकृत्यायन जी की पुस्तक 'वोल्गा से गंगा' और अज्ञेय जी की 'अरे यायावर रहेगा याद' को बचपन में पढ़ने का मौका मिला था। मेरे लिए इनकी सभी कृतियों से अधिक रोचक और बोधगम्य थी ये दोनों कृतियां। यायावरी के अनुभव ने इनके वृत्तांतों को चिरंतन बना दिया है। इन दोनों से प्रेरणा पाकर मैं देश और विदेश की यात्रा कर अपने अनुभव और अध्ययन का दायरा बढ़ाते रहता हूँ। मुझे वो जगह ज्यादा पसंद है जिनका अपना इतिहास है क्योंकि "अतीत के प्रगतिशील प्रयत्नों को सामने लाकर पाठकों के हृदय में आदर्शों के प्रति प्रेरणा पैदा की जा सकती है।"

राहुल जी घुमक्कड़ी के बारे में कहते हैं "मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊँचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव-वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन, क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था, यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता।"

यात्राएं न सिर्फ खुशी देती हैं बल्कि सुनी-सुनाई बातों को सही या गलत के रास्ते पर ले जाती है। जैसे कि मुझे खजुराहो में घूमने के दौरान पता चला कि लोग यहाँ की कलाकृति के बारे में कितना गलत सोचते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है जहाँ जाने के लिए दिल्ली से एकमात्र ट्रेन, कुरुक्षेत्र खजुराहो एक्सप्रेस है जो शाम में नई दिल्ली से चल कर सुबह खजुराहो पहुँच जाती है। खजुराहो छतरपुर जिला के राजनगर तहसील में है जिसकी जनसंख्या लगभग 17000 है। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर औसत जाने और आने वाले यात्री 1100 और 1400 प्रतिदिन हैं। हमारा सफर खजुराहो स्टेशन पर पहुँते ही शुरू हुआ क्योंकि हम



लोग रेलवे रिटायरिंग रूम में ठहरे थे। रिटायरिंग रूम ऐसे कमरे हैं जो पूरे भारत के अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध हैं, वे एसी और नॉन एसी संयोजन के साथ सिंगल, डबल बैड और शयनगृह में उपलब्ध हैं। ये साफ-सुथरे और काफी किफायती होते हैं और इनकी बुकिंग ऑनलाइन होती है।

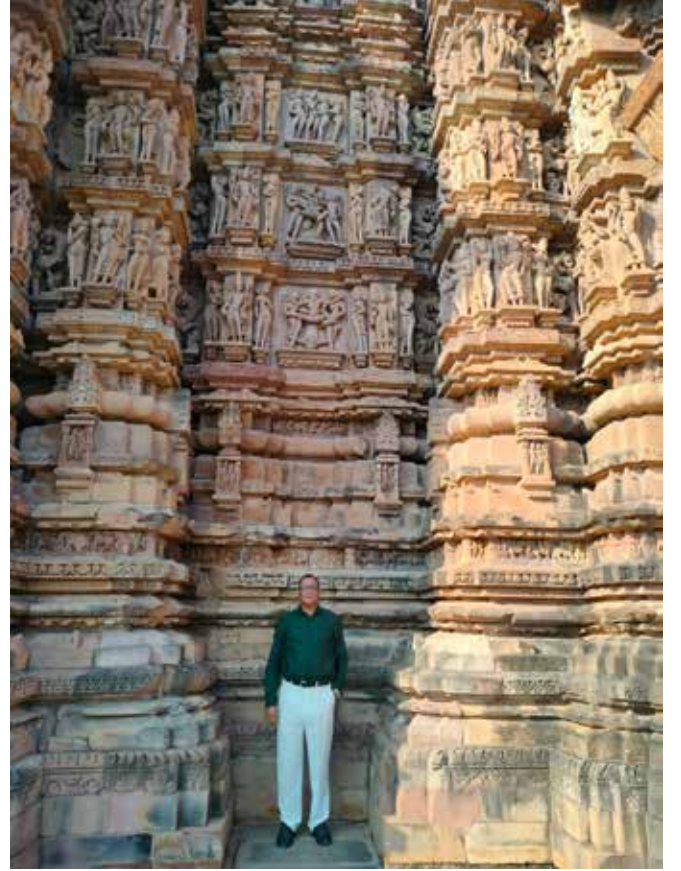
घूमने के लिए बहुत सी टैक्सी स्टेशन पर ही थी। स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। ₹1100 में हम लोगों ने दिनभर के लिए स्विफ्ट डिसाइर बुक की। उसके बाद जो हम लोगों ने

देखा वो सब कुछ जेहन में एक फिल्म की तरह बार-बार चलता है। जब हम लोग निकले तो चारों तरफ धूप निकल आई थी। रास्ते में बहुत सारे होटल दिखाई दे रहे थे और लोग बुंदेली बोल रहे थे जो समझ आ जाती है। रास्ते में कुछ खजूर के पेड़ भी दिखे। यहाँ कभी खजूर के पेड़ बहुत होते थे उसी से इस जगह का नाम खजुराहो पड़ा। कुछ ही देर में हम लोग पश्चिमी मंदिर समूह के गेट से टिकट लेकर प्रवेश कर गए। पहली नजर में दूर-दूर तक बड़े मंदिर दिखाई दिए। अंदर घुसते ही सबसे पहले एक बोर्ड मिला जिस पर खजुराहो के बारे में लिखा था।

यहाँ भारत के शिल्पकारों ने अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक से, नौवीं से ग्यारहवीं सदी के बीच में, ऐसी संरचनाओं का निर्माण किया जो अद्वितीय हैं। इनको चंदेल राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। चंदेल शासकों का उदय आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में 9वीं सदी में हुआ था। चंदेल वंश की स्थापना 831 ईसवी में नन्नुक ने की थी। पहले चंदेल शासक प्रतिहारों के सामंत थे। बुंदेलखंड को ही पहले जेजाभुक्ति के नाम से जाना जाता था। नन्नुक के पौत्र जयसिंह के नाम पर इसका नाम जेजाभुक्ति पड़ा था। इनकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहो में 85 मंदिर बनवाए थे लेकिन अब सिर्फ 22 ही बचे हैं। ये बचे हुए मंदिर इतने भव्य और शानदार हैं कि इतने सालों बाद भी आज भी उनकी कला सलामत है और विश्वभर में मशहूर है।

चंदेल शासकों ने ही सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग अपने लेखों में किया था। लेखों में इनकी उत्पत्ति चन्द्रमा से बताई गयी है। इस कथा के अनुसार काशी शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी का नाम था हेमावती। हेमावती सौंदर्य में सबसे आगे थी। बेहद खुबसूरत हेमावती एक बार नदी में नहाने गयी। जब वो नहा रही थी तब चाँद यानी चन्द्र देव ने उनको देखा। चन्द्र देव हेमावती के सुंदरता पर इतने मंत्रमुग्ध हो गए उन्होंने मन ही मन उसे अपना बनाने का इरादा कर लिया। एक बार वो हेमावती के घर वेश बदलकर गए और उसको अगवा कर लिया। जब हेमावती चन्द्र देव के साथ रहने लगी तब दोनों को एक-दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों के पुत्र ने चंदेल वंश की शुरुआत की। खजुराहो के लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन की आवाज में कही गई ये बातें आज भी जेहन में गूँजती हैं।

जिन देवालयों के प्रांगण कभी खाली नहीं होते थे उन्हें सिकंदर लोधी समेत कई मुसलमान शासकों ने नष्ट कर दिया। ज्यादातर मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। किसी के हाथ नहीं हैं, किसी मूर्ति का पैर नहीं है। ये सिर्फ एक मंदिरों में नहीं है, सभी मंदिरों का यही हाल है।



ऐसा इसलिए है क्योंकि मुस्लिम शासकों ने बार-बार इन मंदिरों को तोड़ा जिससे आज भी उन हमलों की गवाही देती हैं ये टूटी-फूटी मूर्तियाँ। इन मंदिरों को समय के साथ-साथ भूला दिया गया और ये जंगल के आगोश में समा गए। वर्ष 1838 में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन टी यूस बर्ड ने इन्हें खोजा और इनका परिचय पूरे विश्व से कराया। इस तरह समय ने, इस मुकद्दस मुकाम को बनते, उजड़ते और फिर बनते देखा है। हालांकि मंदिरों के दीवारों पर उकेरी गई नब्बे प्रतिशत मूर्तियाँ प्राचीन भारत के जीवन और पौराणिक घटनाक्रम पर आधारित हैं पर दस प्रतिशत कामुक मूर्तियाँ सबसे ज्यादा मशहूर हुईं। इन संरचनाओं में काम शास्त्र के ज्ञान के साथ विज्ञान भी छिपा है और जिसने भी खजुराहो को जान लिया वो जीवन को जान जाएगा।

इन दिव्य देवालयों में जीवन का हर रस अपने उल्लास लिए हुए हैं। एक हजार साल पहले वो लोग शायद हमसे ज्यादा उदार और खुले विचार वाले थे और मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को शायद बेहतर ढंग से समझते थे। यहाँ की कई मूर्तियों में सुडौल शरीर वाली देवियों को दिखाया गया है जो श्रृंगार करती या अपने पाँव में चुभा कांटा निकाल रही हैं लेकिन कुछ

अन्य मूर्तियों में देवी या देवियों को कामुक मुद्राओं में उसी तरह दिखाया गया है जैसे कई अन्य संस्कृतियों में पुरुषों को युद्ध करते दिखाया गया है। इन मंदिरों को देखकर लगा कि इनके रोम-रोम में व्याप्त है अनेक शिल्पकारों की शिल्पसाधना। विशाल इमारत, जोड़ो, गुरुत्वाकर्षण और संतुलन से खड़े हैं। भारी-भारी पत्थरों को काट-काट कर एक-दूसरे पर बैठाए गए हैं।

वर्ष 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल मंदिरों को पश्चिम, पूर्व और दक्षिण समूह में बांटे गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मंदिर पूर्व से पश्चिम की ओर बने हैं। पूर्व के पाँच मंदिर जैन मंदिर हैं जबकि शेष मंदिरों में दस विष्णु को, आठ शिव को, एक सूर्य को तथा एक चौसठ योगिनी को समर्पित हैं।

हर मंदिर दूर से एक जैसे ही लग रहे थे लेकिन सबकी अलग खासियत है। दूर से अगर इन मंदिरों को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये मंदिर चंदन की लकड़ी से बने हुए हैं। इन मंदिरों के इतिहास के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हैं। एक मान्यता के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण शिव शक्ति संप्रदायों के प्रसार के लिए किया गया था। दूसरी मान्यता है कि मंदिर उन देवदासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें मगध, मालवा और राजपूतना से लाया गया था और जो मंदिर की गतिविधियों का प्रमुख भाग थीं। कुछ लोग कहते हैं कि सुर-सुंदरिया जो मंदिर के बाहरी और आंतरिक दीवारों पर उकेरी गई है उन्हें वास्तविक जीवन से लिया गया है। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि मंदिर में उकेरी गई मूर्तियाँ एक सामान्य मनुष्य के जीवन-चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके निर्माण का कोई



दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, फिर भी हमने खजुराहो का मंदिर के रूप में एक वास्तुशिल्प चमत्कार प्राप्त किया है और इसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है।

मंदिर के पश्चिमी समूह में प्रवेश करने पर सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर देखने को मिला। यह मंदिर विष्णु भगवान जी को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 930 से 960 ईसवी के बीच चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा किया गया था। इस मंदिर की दीवारों पर देवी-देवताओं की प्रतिमाएं, सुर बालाओं की प्रतिमाएं और कामुक प्रतिमाएं देखने के लिए मिलती हैं। लक्ष्मण मंदिर के सामने वराह मंदिर (900-925 ईसवी) बना हुआ है। इस मंदिर में विष्णु भगवान के वराह अवतार की प्रतिमा देखने को मिलती है। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। चंदेलों के सबसे प्रतापी राजा



यशोवर्मन ने इसका निर्माण तब कराया था जब उन्होंने प्रतिहारों से कालिंजर छीन लिया और प्रतिहार राजा देवपाल को पराजित किया। ये मंदिर शायद उनकी विजय का प्रतीक है।

कंदारिया महादेव मंदिर, खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है जो अपनी वास्तुकला की भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। कंदारिया का अर्थ होता है "गुफा" और महादेव भगवान शिव का एक नाम है। यह मंदिर 1025 से 1050 ईसवी के मध्य बना है। कंदारिया मंदिर की दीवारों पर विशिष्ट बलुआ पत्थर से बनी संरचना की कामुकता का कलात्मक प्रतिनिधित्व हमारी सांस्कृतिक को एक नया दृष्टिकोण देता है। कंदारिया महादेव मंदिर की ईमारत का निर्माण करवाने वाला विद्याधर बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली शासक था। इस शासक ने 1019 ईसवी के आक्रमण में गजनी के मुहम्मद महमूद गजनवी के साथ लड़ाई की थी लेकिन इस लड़ाई का कोई निर्णय नहीं निकला जिसके बाद मुहम्मद को वापस जाना पड़ा। मुहम्मद ने वर्ष 1022 में विद्याधर के खिलाफ फिर से युद्ध किया और उसने कालिंजर के किले पर हमला कर दिया लेकिन वो किले की घेराबंदी में असफल रहा। इसके बाद विद्याधर ने मुहम्मद से जीत की खुशी में कंदारिया महादेव मंदिर की ईमारत का निर्माण करवाया। अमिताभ बच्चन जब अपनी आवाज में इस मंदिर की कहानी बताते हैं तो बड़ा रोमांच होता है।

विश्वनाथ मंदिर, खजुराहो का पश्चिमी समूह का एक मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है।

प्रतापेश्वर मंदिर, शिव भगवान जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण छतरपुर के तत्कालीन राजा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 1784 से 1854 ईसवी के दौरान करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण राजा प्रताप सिंह के नाम पर प्रतापेश्वर मंदिर पड़ा। यह मंदिर मध्ययुगीन वास्तुकला का अंतिम चरण का उदाहरण है जिसमें चंदेल कला के कुछ अंश देखे जा सकते हैं। मतंगेश्वर मंदिर, खजुराहो का एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। यह खजुराहो के मंदिरों में पूज्य माना जाता है तथा वर्तमान में भी यहां पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण 900 से 925 ईसवी के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। चौसठ योगिनी मंदिर, खजुराहो का स्थित सबसे पुराना मंदिर है जो गोलाकार न हो कर आयताकार है। यह भारत का सबसे पुराना योगिनी मंदिर माना जाता है। यह मंदिर ज्वालामुखी के पत्थरों से बना हुआ है और अब खंडित अवस्था में है, जो मूर्तियाँ यहां प्राप्त हुई थी उन्हे खजुराहो संग्रहालय में रखा गया है।

शिव सागर झील, खजुराहो में प्रसिद्ध है। खजुराहो के पश्चिमी समूह के मंदिर शिव सागर झील के किनारे ही बने हुए हैं। अंग्रेज ऑफिसर जनरल एफ सी मैसी ने वर्ष 1852 में इसका रेखा चित्र बनाया था जो अब ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में रखा हुआ है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हमलोग पूर्व समूह के मंदिरों की ओर चल पड़े। 1050 से 1075 ईसवी के बीच वामन मंदिर का निर्माण किया गया था। विष्णु के अवतारों में इसकी गणना की जाती है। इन दोनों मंदिरों के नजदीक ब्रह्मा मंदिर हैं जिसकी स्थापना 925 ईसवी में हुई थी। इस मंदिर में एक चार मुंह वाला लिंगम है। ब्रह्मा मंदिर का संबंध ब्रह्मा से न होकर शिव से है। यह उस संक्रमण काल की मंदिर है, जब बलुवे पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हो गया था किंतु ग्रैनाइट का प्रयोग पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ था। जैन मंदिर एक कम्पाउंड में स्थित है। जैन मंदिरों को दिगम्बर सम्प्रदाय ने बनवाया था। यह सम्प्रदाय ही इन मंदिरों की देखभाल करता है। इस समूह का सबसे विशाल मंदिर तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। जैन समूह का अंतिम शान्तिनाथ मंदिर ग्यारहवीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर में यक्ष दंपति की आकर्षक मूर्तियाँ हैं।

दक्षिण समूह के मंदिरों में दुलादेव मंदिर है और दूसरा विष्णु से संबंधित है जिसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। दुलादेव मंदिर खुहर नदी के किनारे स्थित है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण 1100 ईसवी में किया गया था। इसके गर्भ में 9 फुट ऊंची विष्णु की प्रतिमा को संत के वेश में दिखाया गया है। बलुवे पत्थर से निर्मित खजुराहो का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है, जिसमें मिथुन प्रतिमाओं का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। सामान्य रूप से इस मंदिर की शिल्प-कला अवनति का संकेत करती है। मूर्तियों के आभूषण के रेखांकन मात्र हुआ है और इनका सूक्ष्म अंकन अपूर्ण छोड़ दिया है। ये सारी विशेषताएँ मंदिर के परवर्ती निर्माण सूचक हैं।

रात में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखकर ये यात्रा एक दिन में ही समाप्त हो गई। हमें उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए जिसे हम जानना चाहते थे। हमें यह पता चल गया कि खजुराहो के मंदिर बेहद परिपक्व और संवेदनशील समाज की देन हैं। भारत के बनने से संबंधित दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड लौकिक इच्छा से बनाया गया था और कामुकता को पवित्र माना गया था। जिस प्रकार कामुकता को दिखाना भारतीय संस्कृति में संभव हो सका है उतना पश्चिमी या किसी अन्य संस्कृतियों में नहीं हो सका।

सेवानिवृत्त महाप्रबंधक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया



बलविंदर कुमार

भारत में ग्रीन फाइनेंस

सतत विकास, पर्यावरण न्यायशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। जलवायु परिवर्तन के आसन्न खतरों से निपटने के लिए विभिन्न शिखर सम्मेलनों ने सतत विकास की तर्ज पर अपनी कार्य-योजनाओं को बनाया है। वर्ष 2030 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) सत्रह समयबद्ध लक्ष्यों का एक अनूठा समूह है जिसका उद्देश्य स्थिरता के सभी तीन उद्देश्यों अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को संतुलित करना है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए स्थिरता एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभरी है। वित्तीय क्षेत्र विशेष रूप से पर्यावरण स्थिरता की दिशा में योगदान करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में वैश्विक स्तर पर कार्पोरेट के बीच 'ग्रीन फाइनेंस' एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है।

हरित-वित्त का अर्थ उन सभी सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को शामिल करना है जो सतत विकास पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ पहलों में जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई और कार्बन तटस्थता शामिल हैं। हालाँकि, जिस संदर्भ में हरित वित्त लागू होता है, वह संबंधित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। विकसित राष्ट्रों के पास स्थिरता संचालित पहलों को वित्तपोषित करने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन हैं जबकि विकासशील देशों को अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों के वित्तपोषण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हरित वित्त के लिए एसोसिएशन ऑफ साउथ



ईस्ट एशियन नेशन की मांग के अनुसार वर्ष 2030 में तीन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में, विकसित देशों ने प्रयासों को अपनाने और कम करने के लिए 2020 तक सौ बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के लिए प्रतिबद्ध किया लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। विकासशील देशों को वित्तीय सहायता के लिए विकसित देशों की आवश्यकता को दोहराया गया। भारत जैसा विकासशील देश हरित वित्त की ओर कदम बढ़ा रहा है।

राष्ट्रीय प्रयास

भारत ने कार्बन तटस्थता के लिए अपनी यात्रा शुरू की है और 2070 तक हासिल करने के लिए 'ग्रीन डील' को आगे बढ़ाया है। ग्रीन डील ने हरित वित्त को डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए एक सक्षम के रूप में वर्गीकृत किया है। यह हरित बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सरकार और निजी संस्थाओं से पूंजी के प्रवाह में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर देता है। इसने

भारत में हरित वित्त की प्रगति में तेजी लाने में मदद करने के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों को तैयार किया है। सबसे पहले, एक स्पष्ट टोस वर्गीकरण हरित परियोजनाओं के विकास के लिए पथ प्रदान करता है और लेनदेन लागत को कम करता है। दूसरे, भारत में कार्बन के मूल्य निर्धारण के लिए ढांचा तैयार करना। कार्बन का मूल्य निर्धारण यह सुनिश्चित करेगा कि जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन रणनीतियों की लागत को निवेश की मुख्यधारा में लाया जाएगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) को शामिल करके राष्ट्रीय निवेश का तीसरा उपयोग जिसमें बॉन्ड के लिए बाजार और ग्रीन फाइनेंस के लिए उपकरण शामिल हैं। अंत में, भारत में हरित वित्तपोषण में बाधा डालने वाले बाहरी उधारी के लिए दिशा-निर्देशों और किसी भी अन्य नियामक बाधा को कम करके वैश्विक बाजारों में कदम रखना।

भारतीय वित्तीय क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र हरित वित्त के विकास में सबसे आगे रहा है। सन 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें बैंकों के महत्व और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता बताई गई थी। इस पृष्ठभूमि में भूमध्य रेखा सिद्धांतों का संदर्भ दिया गया था जो परियोजनाओं का मुद्रीकरण करते समय पर्यावरण और समाज के संबंध में जोखिमों को पहचानने, प्रबंधित करने और मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। 2016 में, आरबीआई को मजबूत वित्तीय प्रणालियों की तर्ज पर यूएनईपी और भारत के सहयोग से एक रिपोर्ट जारी करने का अवसर मिला। रिपोर्ट भारत में वित्तीय प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं और हरित वित्त को तेज करने में इसकी भूमिका की पड़ताल करती है। कानूनी ढांचे के एक भाग के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 बड़ी पूंजी कंपनियों को अपने लाभ का दो प्रतिशत सालाना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योजनाओं के लिए अनिवार्य करता है जिसमें पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास और शिक्षा शामिल है।

भारत सरकार ने संस्थाओं को हरित उत्पादन की दिशा में चलाने के लिए कई योजनाएं और धन सामने रखा है। "Perform Achieve and Trade" योजना के माध्यम से देश के नीतिगत ढांचे में कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत की गई है। सरकार ने हरित ऊर्जा में परिवर्तन की दिशा में अपने मिशन में विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास पर भी जोर दिया है। आरबीआई ने अक्षय परियोजनाओं के लिए संस्थाओं द्वारा ₹10 लाख तक ऋण देने का भी समर्थन किया है। निजी व्यक्तियों के लिए सीमा ₹15 करोड़ तक है। 2021 में आरबीआई नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम



(NGFS) के सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक समूह है जो वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु संबंधी जोखिमों की प्रगति को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के माध्यम से हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण का समर्थन करता है।

स्थायी प्रथाओं की तर्ज पर व्यवसाय चलाने के लिए सेबी बार-बार विभिन्न स्थायी रिपोर्टिंग मानकों के साथ सामने आया है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के आधार पर सबसे पहली रिपोर्टिंग ढांचा 'वार्षिक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग' था। सिद्धांत के मूल तत्वों में से एक में व्यवसायों द्वारा पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक प्रणाली का विकास शामिल है जो आधिकारिक संचालन करते समय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। 'व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट' एक अन्य रिपोर्टिंग ढांचा है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी तरीके से संस्थाओं का संचालन करना है। ढांचा एक प्रकटीकरण मॉडल प्रदान करता है जिसका उपयोग व्यवसायों द्वारा रिपोर्टिंग क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन को देखने के लिए किया जा सकता है। 'पर्यावरण' के सिद्धांत में संस्था द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आठ दिशानिर्देश हैं। इनमें शामिल हैं, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का हिस्सा, कुल ऊर्जा खपत, ऊर्जा बचत विधियों का रोजगार और ऊर्जा की बचत की मात्रा, पानी की खपत और बचाया और पुनर्नवीनीकरण पानी की मात्रा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और कमी, निर्वहन से पहले पानी का उपचार और जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 2021 में सेबी (SEBI) ने एक पहल की और पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ESG) मानकों में प्रकटीकरण को बढ़ाने के लिए 'व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट' (BRSR) को आगे रखा। बीआरएसआर, शीर्ष एक हजार कंपनियों पर लागू है और वित्तीय वर्ष 2022-23 से अनिवार्य है। व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR), ढांचा वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (GRI) जैसे अंतरराष्ट्रीय, सामाजिक और अभिशासन (ESG) मानकों का उपयोग

करता है और प्रस्तुत डाटा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। यह अनुमान लगाया गया है कि निफ्टी 50 में ईएसजी डेटा जिसमें से चालीस प्रतिशत निजी कंपनियों का बड़ा अनुकूल रिकॉर्ड है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2023 तक ग्रीन बॉन्ड का बाजार दो ट्रिलियन डॉलर से अधिक का हो सकता है। ग्रीन बॉन्ड आमतौर पर सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी अन्य बॉन्ड की तरह जारी किए जाते हैं लेकिन आय का उपयोग उन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और शुद्ध शून्य का समर्थन करें। भारत ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से 2015 में ग्रीन बॉन्ड में निवेश करना शुरू किया। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) एक प्राथमिक संस्था है जो हरित बांड जारी करने और सूचीबद्ध करने की आवश्यकताओं को नियंत्रित करती है। 2018-2020 से भारतीय वित्तीय बाजार में ग्रीन बॉन्ड की हिस्सेदारी सिर्फ 0.7 प्रतिशत है लेकिन अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे विकसित देशों की तुलना में अधिक है। भारत में ग्रीन बॉन्ड की निरंतर वृद्धि रही है और 2021 की पहली छमाही में लगभग छह बिलियन डॉलर जारी किए हैं। भारत अपतटीय ग्रीन बॉन्ड फंडिंग की खोज कर रहा है जो शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंतर को पाटने में मदद कर सकता है। भारत में स्थित एक विचारक का अनुमान है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को 10.103 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना होगा। लक्ष्य दो रणनीतियों द्वारा प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है— कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण और हरित

हाइड्रोजन द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी में निवेश। भारत में शीर्ष अक्षय ऊर्जा कंपनियों जैसे अदानी, पावर फाइनेंस कंपनी ने दस वर्षों में परिपक्वता के साथ ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं और विश्व बैंक ने भी विभिन्न उदाहरणों में भारतीय ग्रीन बॉन्ड में निवेश किया है।

भारत पिछले कुछ वर्षों से हरित परियोजना के वित्तपोषण के दौर से गुजर रहा है और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी प्रथाओं को शामिल करने के लिए देश की वित्तीय प्रणाली में तेजी से बदलाव किए गए हैं। व्यवसाय अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और व्यवसाय संचालन में स्थायी तरीके कार्बन तटस्थता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण हैं। कहा जा रहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों की सहायता करने की जिम्मेदारी विकसित देशों की है। सतत प्रयास किए जा रहे हैं जैसे कि कनाडा और जर्मनी द्वारा एक नई जलवायु योजना तैयार करना, जिसमें 2020-25 से उत्पन्न औसत वित्त को शामिल करके सालाना सौ बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संबंध में, कार्बन तटस्थ उद्योगों को ऋण प्रदान करने और पर्यावरण के अनुकूल ऋण अपनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय नीतियां पेश की गई हैं। 2021 तक, सामाजिक और अभिशासन (ESG) और ग्रीन बॉन्ड ने 2020 में एक बिलियन से अधिक की तुलना में लगभग सात बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। पर्यावरण संबंधी सावधानी के गैर-अनुपालन की स्थिति में व्यावसायिक जोखिम से संबंधित जागरूकता पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

—प्रबंधक

अंचल कार्यालय गुरदासपुर
पंजाब

प्रतिक्रिया

हमें तिमाही पत्रिका राजभाषा 'अंकुर' का सितंबर 2022 अंक प्राप्त हुआ जिसमें राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के लेखों का संकलन किया गया है। पत्रिका में बैंकिंग संबंधी लेख, पर्यावरण संबंधी लेख तथा राजभाषा कार्यक्रम से जुड़े लेखों और छायाचित्रों से अंकुर पत्रिका को अत्यंत सुंदर और प्रशंसनीय छवि प्राप्त होती है। पत्रिका में प्रस्तुत लेखों के माध्यम से हमें ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होती है। पत्रिका में 'ग्राहक के मुख से' संबंधी लेख अत्यंत सराहनीय हैं, इस माध्यम से हमारे बैंक ग्राहक भी इस पत्रिका से जुड़ते हैं और उनकी अपेक्षित प्रतिक्रिया भी हमें प्राप्त होती है।

पत्रिका में हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी लेखों को जारी कर उनका हिंदी अनुवाद कर उस भारतीय भाषा का भी प्रसार होता है जो हम नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए 'कल्लू ची आई' लेख के हिंदी अनुवाद को पढ़कर मुझे मराठी भाषा के कुछ वाक्यांश और शब्द सीखने को मिले। पत्रिका को मनोरंजक बनाने हेतु 'कार्टून कोना' भी एक अच्छी पहल है। वास्तव में पत्रिका को उचित साज-सज्जा देने और सराहनीय लेखों से संकलन के लिए राजभाषा विभाग को उनके अच्छे प्रयास के लिए मेरी ओर से अनेक शुभकामनाएं और साधुवाद!

—तारा चंद मीणा
आंचलिक प्रबंधक, बरेली

नराकास उपलब्धियां



नराकास नोएडा (बैंक) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारे अंचल कार्यालय नोएडा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।



राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए नराकास मेरठ द्वारा शाखा-बेगम ब्रिज, मेरठ के मुख्य प्रबंधक श्री विकास तोमर को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया।



नराकास गतिविधि

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मेरठ के तत्वावधान में हमारी शाखा बेगम ब्रिज, मेरठ द्वारा 13 दिसंबर, 2022 को "राजभाषा हिंदी, भारतीय रिजर्व बैंक एवं समसामयिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नराकास मेरठ के सदस्य कार्यालयों से कार्मिकों ने सहभागिता की।

नई शाखाएं

बैंक ने अक्टूबर तथा नवंबर, 2022 माह में तीन नई शाखाएं प्रारंभ की है। इनमें में से दो शाखाएं राजस्थान और अन्य एक शाखा बिहार में खोली गई है।



राजस्थान के नगाऊ (नोहर) जिला हनुमानगढ़ और शैतान सिंह नगर, फलोदी, जिला जोधपुर की शाखाओं का उद्घाटन बैंक के निदेशक श्री शंकर लाल अग्रवाल तथा अंचल प्रमुख श्री सुधीश बाजपेयी द्वारा क्रमशः 11-12 अक्टूबर, 2022 को किया गया।



बिहार में मधुबनी जिले के आंध्रमठ शाखा का उद्घाटन संसद सदस्य श्री रामप्रीत मंडल के कर कमलों से किया गया। बैंक के महाप्रबंधक श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर, लौकहा (बिहार) के विधायक भारत भूषण मंडल, बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन विभाग के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राँय और ऑचलिक प्रबंधक कोलकाता श्री ललित कुमार शर्मा इस अवसर पर उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार



बैंक के अंचल कार्यालय बठिंडा को वर्ष 2021-22 के दौरान संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उत्तर क्षेत्र-1 का "ख" क्षेत्र में बैंकों की श्रेणी में "प्रथम पुरस्कार" प्रदान किया गया। देश की स्वर्ण नगरी अमृतसर में 03 नवंबर, 2022 को आयोजित उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में आँचलिक प्रबंधक श्री पवन कुमार भाटिया तथा अंचल कार्यालय बठिंडा में पदस्थ प्रबंधक (राजभाषा) श्री सुशील कुमार ने पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र ग्रहण किए।

१९६१ प्रो. वगविवतु नी वी इउरि

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
की ओर से

नव वर्ष 2023
की हार्दिक
शुभकामनाएँ

इस नए वर्ष का उत्सव नए उत्पादों के शुभारंभ के साथ मनाएं
बैंक सहर्ष प्रारंभ कर रहा है

<p>पूर्णयता डिजिटल एफ डी उत्पाद</p> <ul style="list-style-type: none">पीएसबी यूनिट द्वारा 601 दिन एफ डी ऑनलाइन खोलेब्याज दर: 8.10% (अति वरिष्ठ नागरिक) 7.75% (वरिष्ठ नागरिक) 7.25% (सामान्य)	<p>पूर्व-स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण</p> <ul style="list-style-type: none">'3 क्लिक' पर डिजिटल मंजूरीत्वरित ऋण, आकर्षक ब्याज दर एवं शून्य प्रोसेसिंग शुल्क*	<p>पीएसबी यूनिट* द्वारा ऑनलाइन बचत खाता खोलें</p> <p>त्वरित पीएसबी यूनिट पंजीकरण एवं वर्चुअल कार्ड</p> <p>शून्य बैलेंस खाता</p>	<p>4 चार नए मिड-कोर्पोरेट शाखाएं</p> <ul style="list-style-type: none">अहमदाबादबैंगलूरुकोलकातालुधियाना
--	---	--	--

*नियम एवं शर्तें लागू

साथ में पीएसबी एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का भी शुभारंभ

“बड़े इनाम, बड़ी बचत”



पीएसबी UniC
डाउनलोड के लिए क्यूआर
कोड स्कैन करें



पीएसबी UniC
डाउनलोड के लिए क्यूआर
कोड स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें,
हमारी वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in> देखें

ईमेल ho.customerexcellence@psb.co.in

1800 419 8300 (टोल फ्री) | @PSBndOfficial हमें फॉलो करें

